हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 210 बेमेतरा, बुधवार 25 मार्च 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

विमान दुर्घटना: 125 सवारों में से 66 की मौत, कई को बचाया गया

बोगोटा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के पुटुमायो प्रांत में वायुसेना का एक हरक्यूलिस सी-130 परिवहन विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में कम से कम 66 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय मीडिया में वायुसेना के हवाले से यह जानकारी दी गयी है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस दुर्घटना के शिकार हुए कई सैन्य कर्मियों को बचा भी लिया गया है और करीब दो दर्जन लोगों के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। यह लड़ाकू विमान नहीं है बल्कि यह एक मालवाहक विमान है जिसका उपयोग सैनिकों और साजोसामान की आवाजाही में किया जाता है। वायुसेना कमांडर जनरल कार्लोस फर्नांडो सिल्वा रुएडा के अनुसार, विमान में सेना के 114 जवान और चालक दल के 11 सदस्यों सहित कुल 125 लोग सवार थे।

सुरक्षा बलों के लिये 22 हजार करोड़ की मांग डबल इंजन सरकार की हकीकत : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदो को डिनर में बुलाया था। एक छोटी सी मीटिंग भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने सांसदो से यह अनुरोध किया कि जो छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय सुरक्षा बल नक्सल क्षेत्र में तैनात है, उसका लगभग 22 हजार करोड़ रू. की राशि केन्द्र सरकार को राज्य से देना है। इसमें छूट के लिये वह पहल करे और केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव बनाये, इस मामले को सदन में भी उठाया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार की हकीकत को दिखता है। भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता से वादा किया था कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास कार्य तेज होंगे और यहां पर डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री को अपने केन्द्र सरकार से ही केन्द्रीय राशि में छूट देने के लिये मिन्नतै करनी पड़ रही है, वो भी नक्सलवाद जैसे विषय में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नक्सलवाद से निपटना केन्द्र और राज्य दोनों का काम है।

मुख्यमंत्री साय लगभग 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 500 करोड़ रुपये की सौगात देंगे

रायपुर। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर और सबसे कम बीजापुर जिला से 1542 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़कर यह संदेश दिया है कि 'अंत्योदय' की कतार में खड़ा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भी शासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजनाके तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है।

25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राशि अंतरित करेंगे, तो वह छत्तीसगढ़ के न्याय और सुशासन की गूंज होगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो, तो विकास की किरण हर झोपड़ी तक पहुंचती है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। संकल्प बजट 2026-27 में 600 करोड़ रूपए का

प्रावधान के साथ भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का सशक्त संबल मिलेगा। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर, बिलासपुर जिला के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिला के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूर और सबसे कम बीजापुर जिला से 1542 भूमिहीन कृषि मजदूर, कोरिया जिला से 1549 भूमिहीन कृषि मजदूर और नारायणपुर जिला से 1805 भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उददेश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।

इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

पश्चिम एशिया संकट का असर लंबे समय तक रहने की आशंका, हर परिस्थिति के लिए रहना होगा तैयार : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट का असर लंबे समय तक जारी रहने की आशंका जाहिर करते हुए मंगलवार को कहा कि देश को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिये और सरकार पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। मोदी ने राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों जैसे जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने खाड़ी देशों में रहने वाले करीब एक करोड़ भारतीयों के लेकर भी चिंता जाहिर की और बताया कि अब तक खाड़ी देशों से तीन लाख 75 हजार लोगों को निकाला गया है जिसमें ईरान से निकाले गये एक हजार से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने

कहा, इस युद्ध को लेकर पल-पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं कि सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की संसद के ऊपरी सदन से शांति की एकजुट आवाज की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सरकार का उद्देश्य वार्ता और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति बहाली का है।

ट्रंप ने मोदी के साथ पश्चिम एशिया पर की बात, होरमुज जलडमरूमध्य पर भी हुई चर्चा

पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने होरमुज जलडमरूमध्य सहित इस वैश्विक संकट के सभी पहलुओं पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे बात की है और उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर सार्थक चर्चा की। मोदी ने एक्स पर ट्रंप के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप से कॉल प्राप्त हुआ और पश्चिम एशिया की स्थिति पर उपयोगी विचार-विमर्श हुआ। भारत तनाव कम करने और यथाशीघ्र शांति बहाल करने का समर्थन करता है। होरमुज़ जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होरमुज़ जलडमरूमध्य को खुला बनाए रखने के महत्व भी बातचीत हुई। विदेश मंत्री डा एस जयशंकर ने भी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात की थी। दोनों ने इस संकट के अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर भी चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बात की। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया की स्थिति पर वैश्विक नेताओं के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं।

निजता के अधिकारों का उल्लंघन है उभयलिंगी संशोधन विधेयक : विपक्ष

नयी दिल्ली। विपक्षी दलों ने 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026' को व्यक्ति की पहचान को नियंत्रित करने और निजता के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि विधेयक में पहचान को जटिल बनाने का काम किया जा रहा है इसलिए सरकार को इसे वापस लेना चाहिए या संसद की स्थायी समिति को भेजना चाहिए। कांग्रेस की एस ज्योतिमणी ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण(संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विधेयक का विरोध किया और कहा कि विधेयक के जरिए सरकार उभयलिंगी समाज को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। विधेयक के प्रावधान कठोर है और इस विधेयक के ज़रिए उभयलिंगी समाज की पहचान डॉक्टरों के पैनल और नौकरशाही के हवाले कर निजता की पहचान को नौकरशाही के हवाले करने का काम किया जा रहा है और इस समाज उनके लिए समानता की बात बदल जाएगी। उनका कहना था कि सरकार इस विधेयक के जरिए इस समुदाय के अधिकारों को नियंत्रित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधेयक में बहुत सारी कमियां है। इसमें उभयलिंगी समाज के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं इसलिए इस विधेयक को वापस लेकर संसद की स्थायी समिति को सौंपना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने कहा कि उभयलिंगी समाज परंपरा से सम्मान का पात्र रहा है। इस संबंध में उन्होंने राम वनवास का संदर्भ दिया और कहा कि उभयलिंगी समाज के लोग भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त है। उनका कहना था कि महाभारत काल में भी उभयलिंगी समाज ने अपनी महत्ता का प्रदर्शन किया लेकिन मोदी सरकार इस विधेयक के माध्यम से इस समाज को आपराधिक श्रेणी में लाने का काम कर उनके अधिकारों के खिलाफकाम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधेयक में उभयलिंगी की पहचान के लिए मेडिकल टीम बनाने की बात है जो ट्रांसजेंडर का निर्धारण करेगी और फिर जिला अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि व्यक्ति उभयलिंगी है या नहीं, विधेयक उभयलिंगी समाज के खिलाफहै और उनके अधिकारों को सीमित करता है।

प्रस्तावित विधेयक उभयलिंगी की गरिमा और आजादी को भंग करता है और उन्हें नौकरशाही के अधीन पहचान के लिए सीमित अधिकारों में बांध देता है। भदौरिया ने इस विधेयक को अव्यवहारिक बताया और कहा कि सरकार 2019 में इस बारे में विधायक लाई थी लेकिन अब उसमें इतना जल्दी संशोधन भी ला रही है जो गलत है।

एम्स में चिकित्सकों की कमी का मामला सांसद फूलोदेवी ने राज्यसभा में उठाया

रायपुर। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रायपुर एम्स में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफकी कमी का मामला उठाया। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि यदि किसी मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलता तो वह भी इलाज नहीं देने के समान ही माना जाता है। यही हाल रायपुर स्थित एम्स का है, जहां गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने बताया कि एम्स, रायपुर में चिकित्सक के 305 पद स्वीकृत हैं जिसकी तुलना में केवल 190 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, 115 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और सर्जरी विभाग चिकित्सक की कमी से जूझ

रहे हैं। नर्स, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों में लगे स्टाफ के 3 हजार 884 पद स्वीकृत हैं, 2 हजार 387 स्टाफ कार्यरत है, 1 हजार 497 पद खाली पड़े हैं। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने यह भी कहा कि चिकित्सक और सहायक स्टाफ की कमी के कारण ओपीडी में तो लंबी लाईने लगती ही है, बल्कि ऑपरेशन और जांच में भी देरी हो रही है। जब भी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित को भर्ती कराने के लिए कहा जाता है तो वहां पर बैड नहीं है कहकर मना कर देते हैं। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने मांग करते हुए कहा कि एम्स रायपुर में चिकित्सक और अन्य स्टाफ के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए तथा बेड संख्या बढ़ाई जाए।

सरकार के प्रयासों से किसानों की दुगुनी-तिगुनी हो गयी है : शिवराज

नयी दिल्ली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सभा में कहा कि सरकार के प्रयासों से बड़ी संख्या में किसानों की आय दुगुनी-तिगुनी हुई है। चौहान ने प्रश्न काल में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाकर और अन्य सहूलियतें प्रदान कर एक वर्ष में दो से तीन फसलें लेने के उपाय किये हैं, जिससे कई किसानों की आय चौगुनी और आठ गुनी तक हो गयी है। सरकार के गंभीर प्रयासों से यह संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि

बजट एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये का कर दिया गया है। कृषि विभाग से संबंद्ध अन्य विभागों और इकाइयों का बजट जोड़ दिया जाये तो यह पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, तो किसानों की आय भी है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर फ सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है।

अमेरिका-इजरायल के अलावा अन्य देशों के जहाजों को निकलने का रास्ता दिया जाएगा : पेजेशकियान

तेहरान। ईरान ने अमेरिका और इज़रायल को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने की अनुमति देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पेजेशकियान ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ हुई फोन वार्ता में कहा, किसी भी

सूरत में, ईरान ने इस जलमार्ग से जहाज़ों के पार होने के लिए सुरक्षा एवं रक्षा के इंतजाम किये गये हैं। शत्रु देशों को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुज़रने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इज़रायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए।

प्रतियोगिताएं रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित होंगी, कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर, राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मिलेगा बड़ा बढ़ावा : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ आज से शुरू हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव का मानना है कि यह राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बड़ा बढ़ावा देगा। आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साव–जो राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हैं–ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भारतीय खेल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, हमने पहले सरगुजा ओलंपिक और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन छोटे स्तर पर किए हैं। अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी कर हम एक बड़े मंच पर कदम रख रहे हैं, जो हमारी क्षमताओं की परीक्षा भी लेगा और उन्हें नई ऊंचाई देगा। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, यह छत्तीसगढ़ के लिए निस्संदेह एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन है। यह हमारे खेल प्रतिभा और बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती देगा। साथ ही, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन का प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रदान करेगा। भारत के शीर्ष खिलाड़ी–हॉकी ओलंपियन दिलीप तिर्की,

सलीमा टेटे और शीर्ष धावक अनिमेष कुजूर–ने कहा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स खेलों में करियर बनाने और आदिवासी समुदाय से निकले दिग्गज खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने का एक शानदार मंच है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे और कुल नौ खेलों का आयोजन होगा। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती में पदक दिए जाएंगे, जबकि मल्लखंब और कबड्डी प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल होंगे। करीब 3,800 प्रतिभागी इन खेलों में हिस्सा लेंगे, जो 3 अप्रैल तक चलेंगे। प्रतियोगिताएं रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित की जाएंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व ओलंपियन दिलीप तिर्की ने साई मीडिया से कहा, मेरे लिए और हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि देश में पहली बार इस तरह की चैंपियनशिप शुरू हो रही है। यह युवाओं और आदिवासी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और खेलों में आगे बढ़ने, तथा देश के लिए खेलने का एक बेहतरीन अवसर है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि भारत एक खेल राष्ट्र बने। वे चाहते हैं कि हर युवा किसी न किसी खेल से जुड़ा रहे। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और असम से 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुरुष और महिला खिलाड़ियों का अनुपात लगभग 50:50 रहेगा, जो ओलंपिक चार्टर में लैंगिक समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। साव ने कहा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों के साथ खेलने और उन्हें देखने का अनुभव छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए बेहद समृद्ध करने वाला होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आयोजन राज्य के खेल तंत्र और खिलाड़ियों दोनों के लिए बड़ी ताकत साबित होगा। कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। एथलेटिक्स में सर्वाधिक 34 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। तैराकी (24), कुश्ती (18), वेटलिफ्टिंग (16) और तीरंदाजी (10) में भी दो अंकों में स्वर्ण पदक होंगे। हॉकी और फुटबॉल टीम खेल हैं, जिनका आयोजन रायपुर में होगा। एथलेटिक्स जगदलपुर में और कुश्ती सरगुजा में आयोजित की जाएगी।

अमेरिका-इजरायल के हमलों में तेहरान में अब तक 600 लोगों की मौत

तेहरान। इज़रायल और अमेरिका के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान की राजधानी तेहरान में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इरना समाचार एजेंसी ने तेहरान की आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख मोहम्मद इस्माइल तवक्कोली के हवाले से बताया इस दौरान (संघर्ष शुरू होने के बाद से) राजधानी में 636 लोग मारे गए हैं और अब तक 6,848 लोग घायल हुए हैं। तेहरान में लगभग 430 जगहों पर हमले हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने 12 मार्च को कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल के सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप ईरान में 1,348 नागरिक मारे गए और 17,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह अभियान 28 फरवरी को ईरान के कई शहरों में शुरू किया गया था।

, जिसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इसके जवाब में इज़रायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका और इज़रायल ने शुरू में दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से होने वाले कथित खतरे का मुकाबला करने के लिए उनका 'पूर्ववर्ती' हमला ज़रूरी था, लेकिन जल्द ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं।

सैन्य अभियान के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गये। इस्लामिक गणराज्य ने 40 दिनों के शोक की घोषणा की।

प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली जिंदगी, जर्जर झोपड़ी से पक्के मकान तक पहुँची श्रीमती दशोदा धीवर की कहानी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत सरदा, जनपद पंचायत बेरला की रहने वाली श्रीमती दशोदा धीवर के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने एक नई उम्मीद और खुशहाली लेकर आई है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवास का निर्माण कार्य 20 अगस्त 2025 को पूर्ण हुआ, जिसके बाद उनका वर्षों पुराना सपना साकार हो गया।

कच्ची झोपड़ी में गुज़रता था जीवन-आवास मिलने से पहले श्रीमती दशोदा धीवर का घर कच्ची दीवारों और घास-फूस की छत से बना एक जर्जर झोपड़ी था। हर बारिश में छत से पानी टपकता था और दीवारें कमजोर हो जाती थीं। तूफान के समय उन्हें पूरी रात जागकर बितानी पड़ती थी, क्योंकि हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं घर गिर न जाए। गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम उनके लिए बेहद कठिन साबित होते थे और सुरक्षा की चिंता हमेशा बनी रहती थी।

मेहनत-मजदूरी से चल रहा था परिवार-श्रीमती दशोदा धीवर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थीं। उनकी आय अनिश्चित थी और कई बार उन्हें रोज़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक पक्के और सुरक्षित घर का सपना उनके लिए लगभग असंभव जैसा लगने लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी।

निर्माण का सफर रहा चुनौतीपूर्ण लेकिन सफल-आवास निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। उन्हें बैंक खाता खुलवाना पड़ा, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने पड़े और योजना के तहत मिलने वाली राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना पड़ा। शासन द्वारा सहायता राशि किश्तों में सीधे उनके खाते में भेजी गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रही।स्थानीय अधिकारियों के मार्गदर्शन और ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया। पैसे बचाने के लिए उन्होंने खुद भी श्रमदान किया और धीरे-धीरे ईट दर ईट उनका सपना साकार होता गया।

पक्का मकान बना खुशियों का नया आधार-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बने इस नए मकान में मजबूत दीवारें, अच्छी छत और सुरक्षित दरवाजा है। इसके साथ ही उन्हें शौचालय निर्माण की सुविधा मिली और संबंधित योजनाओं के माध्यम से बिजली एवं स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की भी सुविधा उपलब्ध हुई। अब उनका घर भले ही सादा है, लेकिन मजबूत और सुरक्षित है।

आवास बनने के बाद बदला पूरा जीवन-आवास पूर्ण होने का दिन श्रीमती दशोदा धीवर के जीवन के सबसे खुशी भरे पलों में से एक था। उनके बच्चों ने घर के सामने रंगोली बनाकर खुशी जाहिर की और पड़ोसियों ने भी इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। अब उनके बच्चों को सुरक्षित और सूखे वातावरण में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। बेहतर आवास मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम हो गई हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिली है। अब बारिश डर नहीं, खुशी का कारण है- पहले जहां बारिश का नाम सुनकर उन्हें डर लगता था, वहीं अब वह अपने पक्के मकान में सुरक्षित बैठकर बारिश का आनंद लेती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने न सिर्फ उन्हें एक घर दिया है, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान के साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर भी दिया है।प्रधानमंत्री आवास योजना का यह उदाहरण बताता है कि शासन की योजनाएं जब सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे किसी परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 25 मार्च को राशि वितरण कार्यक्रम

जिला मुख्यालय मे मंत्री दयालदास बघेल होंगे मुख्य अतिथि

बेमेतरा/मूक पत्रिका

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा 25 मार्च 2026 को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 25 मार्च को प्रातः 11.00 बजे से संबंधित जनपद पंचायतों के सभा कक्ष में आयोजित किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं तथा अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़

शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल होंगे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक श्री दीपेश साहू और साजा विधायक श्री ईश्वर साहू उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ रजकाकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रह्लाद रजक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा तथा भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अजय साहू सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा जारी आदेश के अनुसार, कार्यक्रम के सफल संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिले के सभी अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं तहसील स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिला प्रशासन के इस निर्णय से भूमिहीन कृषि मजदूरों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का हुआ जिला स्तरीय शुभारंभ

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय शुभारंभ 24 मार्च से जिला ऑडिटोरियम, जांजगीर में किया गया। इसके साथ ही टीबी मुक्त पंचायतों एवं मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को गति देना है। इस दौरान टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित किया गया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर जन्मेजय महोबे, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार साहू, जिला पंचायत सदस्य

लोकेश साहू, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप पाटले, सीएमएचओ डॉ अनिता श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल, डीपीएम उत्कर्ष तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।कलेक्टर ने कहा कि टीबी पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी है, इसके लिए समय पर जांच और नियमित इलाज बेहद जरूरी है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और उपचार पूरा करें। उन्होंने क्षय रोग के विरूद्ध विशेष जागरूकता चलाने एवं स्वयं के द्वारा भी किट प्रदान करने एवं ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुचाने कहा। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर-घर सर्वे, स्क्रीनिंग और उपचार की व्यवस्था किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी टीबी मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया और जनजागरूकता फैलाने का आह्वान किया।इसके साथ ही टी.बी. मुक्त पंचायतों एवं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत सत्र 2024-25 में जिले की मेधावी छात्रा कु. खुशी देवांगन, कु. ज्योति ओग्रे, कु. ईशा, कु. अदिति देवांगन, कु. रोशनी जोगी, कु. पुष्पा चौहान को पुरस्कार प्रदान किया गया।

जनदर्शन ,जन चौपाल के आवेदनों पर करें तत्काल निराकरण की कार्यवाही- कलेक्टर आकाश छिकारा

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, योजनाओं की प्रगति तेज करने पर जोर

जगदलपुर/मूक पत्रिका

जगदलपुर कलेक्टर बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जन दर्शन, सुशासन तिहार, जन चौपाल और समय सीमा के आवेदनों व प्रकरणों पर तत्काल निराकरण करने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से आंगनबाड़ी के बच्चों का आधार अपडेट करवायें, सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों का ई-एचआरएमएस में ऑनबोर्ड की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अवैध अफीम

खेती की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु शासन के निर्देशानुसार जिले में अफीम की अवैध खेती की जांच सभी राजस्व अधिकारियों से कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं रेत खदानों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों से एनओसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने तथा निर्माण विभागों को खनिज रॉयल्टी जमा करने के निर्देश दिए। धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 31 मार्च तक शत-प्रतिशत समितियों से धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भंडारण में चावल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।कृषि क्षेत्र में एग्रीस्टैक के तहत किसानों के पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभागों में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान कार्ड निर्माण, शत-प्रतिशत टीकाकरण, एनआरसी में बेड ऑक्यूपेंसी, सघन मोतियाबिंद जांच एवं जननी सुरक्षा योजना की प्रगति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। रक्तदान शिविर आयोजन, अस्पतालों में इंटरनेट व्यवस्था दुरुस्त करने तथा पोस्टमार्टम की ऑनलाइन रिपोर्ट की व्यवस्था करने पर चर्चा की। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री स्कूलों के निर्माण कार्य, सरस्वती साइकिल योजना तथा अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपोषण अभियान, सुपोषण चैपाल, रेडी-टू-ईट फूड उत्पादन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की स्थिति पर भी चर्चा हुई।बैठक में आवास योजना में पुनर्वासित जनों को लाभ देने, श्रमिक राशन कार्ड, जल जीवन मिशन, सौर सुजला योजना तथा सामाजिक पेंशन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत नक्शा बंटांकन, स्वामित्व योजना, फौती नामांतरण एवं अन्य लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया।इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, नगर निगम आयुक्त श्री प्रवीण वर्मा, सहायक कलेक्टर श्री विपिन दुबे सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे । बैठक में टी बी मुक्त बस्तर जिला बनाने के लिए निक्षय मित्र के रूप राशि देने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र का वितरण कलेक्टर श्री छिकारा द्वारा प्रदान किया गया और टी बी मुक्त बस्तर के लिए शपथ भी दिलाई।

मादा वत्स उन्नत मादा पालन पोषण योजना के 71 हितग्राहियों को वितरित किया गया पशु आहार

प्रत्येक हितग्राहियों को मिला 11 बोरा 23 किलो पशु आहार (दाना)

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

पशुधन विकास विभाग की मादा वत्स (उन्नत मादा) पालन पोषण योजना के तहत विकासखंड सारंगढ़ के 11 हितग्राहियों को जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डे के द्वारा उप संचालक पशुधन डॉ महेंद्र पाण्डेय की अगुवाई में काफ ग्रोवर (दाना) राशन प्रदान किया गया एवं पूरे जिले में 71 हितग्राहियों को काफ ग्रोवर पशु आहार वितरण किया गया है, जिससे इस जिले के हितग्राहियों में अति उत्साह है एवं प्रत्येक हितग्राहियों को 11 बोरा 23 किलो दाना दिया गया।

पशु विभाग के इस कार्य से आम जनता में उत्साह है। इसी तरह का कार्यक्रम बिलाईगढ़ ब्लॉक में कृषि स्थायी समिति सभापति सोनी टंडन एवं समिति के सदस्यों के द्वारा 5 ओबीसी और 5 अनुसूचित जाति हितग्राहियों को कैल्फ ग्रोवर फीड का वितरण किया गया।

सरिया पुलिस की लगातार कार्रवाई: 25 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

अवैध शराब के खिलाफ सरिया पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और सफलता हासिल करते हुए 25 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दबिश-23 मार्च 2026 को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम साल्हेओना, दादरपाली रोड के पास एक व्यक्ति बिक्री के लिए अवैध शराब छिपाकर रखा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बरगद पेड़ के पास घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से काले बैग में 15 लीटर और सफेद प्लास्टिक थैले में

10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई।

आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज-पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजेंद्र यादव (उम्र 20 वर्ष) निवासी साल्हेओना बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 25 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका-यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देश और अति. पुलिस अधीक्षक निमीषा पाण्डेय व डीएसपी संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में की गई।

थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक टीकाराम पटेल, आरक्षक नरेंद्र चंद्रा, श्रवण टंडन सहित समस्त थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही। पुलिस ने साफ किया है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कांग्रेस ने बूथ , पंचायत वार्ड कमेटियों के गठन के लिए नियुक्त किए प्रभारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने बूथ कमेटी निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है । जिला कांग्रेस कमेटी ने बूथ को मजबूत बनाने और बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले के सभी ब्लाकों मे बूथ , पंचायत तथा वार्ड कमेटी गठन प्रभारी की नियुक्ति कर दी है । जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने नियुक्ति आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के अंतर्गत सभी बूथ , पंचायत एवं वार्ड कमेटी का गठन तत्काल प्रभाव से पूर्ण किया जाए ,साथ ही सभी ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि जल्द ही मंडल कमेटियों के प्रभारी नियुक्त कर बूथ निर्माण की प्रक्रिया मे सहयोग प्रदान किया जाए । साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया

है कि बूथ कमेटी का गठन सम्बन्धित बूथ पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति मे सर्वसम्मति से किया जाए , बैठक प्रकिया का फेटो एवं वीडियोग्राफी जिला कांग्रेस को कमेटी को अनिवार्य रूप से भेजी जाए ।गठन प्रक्रिया मे उदयपुर नवाशिविर मे पारित प्रस्ताव का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है । जारी आदेश के अनुसार प्राणीश चौबे उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार थानखम्हरिया, जितेन्द्र उपाध्याय उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार साजा, झम्मन बघेल उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार नवागढ़, मोंटू तिवारी महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार संबलपुर, छोटे लाल साहू उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार नांदघाट, सुमन गोस्वामी महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार (ग्रामीण) बेमेतरा, सतीश मारकंडेय महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार बेरला, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा प्रभार नगर बेमेतरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है ।

गांव में किसान बेबस नजर आए और कंपनी को खुली छूट दे दी गई

गेजामुड़ा में आर-पार की जंग: 'बाउंसरों' और पुलिस छावनी के संरक्षण के बीच अडानी का काम शुरू, विरोध करने वाले दर्जनों ग्रामीण हिरासत में

भारी पुलिस बल, बड़ी मशीनों और 'निजी बाउंसरों' के साये में अडानी का काम जबरन शुरू

प्रशासन ने साफकर दिया है कि कंपनी के काम में जो भी रुकावट डालेगा, उसका अंजाम ऋषि पटेल जैसा ही होगा

रायगढ़/मूक पत्रिका

ग्रामीण ईधर कोतरा रोड थाने के बाहर धरने पर बैठे रह गए।और जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ ग्राम गेजामुड़ा पहुंचकर अडानी कंपनी के रेल लाईन कार्य को प्रारंभ करवा दिया गया।जब प्रदर्शनकारी प्रभावितों को मामले की जानकारी मिली तो उनके द्वारा अपनी भूमि और ही गांव पहुंचकर काम

रुकवाने जा प्रयास किया गया।जहां पुलिस बल द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है।जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल है।

रातभर थाने के बाहर दिया धरना-गौरतलब हो कि ग्राम गेजामुड़ा में अडानी कमानी की रेल लाइन विस्तार में मुआवजे की मांग को लेकर बीते तीन महीनों से जिला प्रशासन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है।पूर्व में भी विरोध जताने वाले तीन ग्रामीणों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रदर्शन को लेकर नोटिस भेजा गया था जहां शनिवार को प्रभावित ग्रामीण ऋषि पटेल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मामला गरमा गया।और ग्रामीणों द्वारा गिरफ्तार ग्रामीण की रिहाई की मांग को लेकर कोतरा रोड थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया।जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा का उन्हें भरपूर सहयोग मिला।रातभर धरना देने के बाद जब रविवार की दोपहर जिला प्रशासन,प्रभावित और कंपनी प्रबंधन के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता की बात पर सहमति बनी तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ही इस वार्ता में कंपनी प्रबंधन की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वही जमीन अधिग्रहण के पूर्व प्रभावित के सहमति नहीं लिए जाने की बात भी कही जा रही है।बहरहाल वर्तमान दर पर मुआवजे का मसला एक बार फिर अनसुलझा रह गया है।

नहीं हुई रिहाई, खरसिया विधायक नहीं दिए दिखाई-ग्राम पंचायत गेजामुड़ा के ग्रामीण जिस व्यक्ति की रिहाई को लेकर रातभर से थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने में लगे थे।उसका कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकल सका।उल्टे रविवार को ग्रामीणों के धरना के दौरान जिला प्रशासन की तुम पुलिस दल बल के साथ ग्राम गेजामुड़ा पहुंची।और बड़ी बड़ी जे सी बी मशीनों के सहारे काम शुरू करवा दिया गया।मामले की जानकारी प्रदर्शनकारियों को लगने पर आनन फान में गांव पहुंचे।और बिना मुआवजा के काम शुरू कर देने पर एक बार फिर विरोध जताया गया।जिस पर पुलिस द्वारा ग्रामीण महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।वही इस दौरान पूर्व मे गिरफ्तार किए गए ऋषि पटेल की धर्मपत्नी ने पुलिस प्रशासन से अपने पति को पहले रिहा कर फिर काम करने अपील की गई।इसे पूरे घटनाक्रम के क्षेत्रीय विधायक उमेश पटेल की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही।जिसे लेकर ग्रामीणों के आक्रोश भी देखने को मिला।जबकि प्रभावित उनके विधानसभा क्षेत्र में ही शामिल है।बावजूद ऐसे संवेदनशील मामले में बड़े जनप्रतिनिधियों की चुप्पी समझ से परे है।गेजामुड़ा रायगढ़ जिले के ग्राम गेजामुड़ा में अडानी की रेलवे लाइन परियोजना को लेकर चल रहा विवाद अब 'आर-पार की लड़ाई' में तब्दील हो गया है। ऋषि पटेल के गिरफ़्तारी की कार्यवाही किसी बड़े 'ऑपरेशन' की पहली सीढ़ी है। आज वही हुआ एडिशनल एसपी के साथ ग्रामीणों की वार्ता विफल होते ही गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी पुलिस बल, बड़ी मशीनों और 'निजी बाउंसरों' के साये में अडानी का काम जबरन शुरू करा दिया गया है। अपनी जमीन बचाने के लिए विरोध करने पहुंचे महिलाओं और पुरुषों समेत दर्जन भर ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।गेजामुड़ा में भारी पुलिस बल और 'बाउंसरों' की मौजूदगी में अडानी रेल लाइन का काम जबरन शुरूएडिशनल एसपी के साथ ग्रामीणों की वार्ता रही विफल, 100त्न मुआवजे की मांग पर अड़े हैं किसान अडानी प्रबंधन केवल 50त्न मुआवजा देने को तैयार, ग्रामीणों ने कहा- मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे शांतिपूर्ण विरोध करने पहुंचे महिलाओं और पुरुषों समेत दर्जन भर से अधिक ग्रामीण पुलिस हिरासत मेंगिरफ्तार किए गए युवा किसान ऋषि पटेल को दोषमुक्त कर रिहा करने की मांग पर भी नहीं बनी बात भविष्यवाणी हुई सच, बड़े प्रशासनिक अमले और मशीनों के साथ गांव में दहशत का माहौल

50% बनाम 100त्न की लड़ाई, वार्ता रही विफल- रविवार दोपहर गेजामुड़ा के हालात को काबू करने के लिए एसडीएम, एडिशनल एसपी और पुलिस के आला अधिकारियों ने कोतरा रोड थाने में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।

मन की मुराद पूरी करने वाली मां मानकादाई, खोखरा गांव में नवरात्रि पर उमड़ती है आस्था की भीड़

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर जिले के खोखरा गांव स्थित मां मानकादाई मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करा रहे हैं। स्वप्न में दर्शन के बाद हुई माता की स्थापना - ग्रामीणों के अनुसार, जिस स्थान पर आज मां मानकादाई विराजमान हैं, वहां पहले घना जंगल और चारों ओर तालाब हुआ करते थे। बताया जाता है कि खोखरा गांव के मालगुजार तिवारी परिवार के एक सदस्य को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर मूर्ति स्थापना का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों के सहयोग से माता की मूर्ति बनवाकर विधि-विधान से स्थापना की गई। तभी से प्रतिदिन सुबह-शाम पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है। तिवारी परिवार की कुलदेवी होने के कारण हर नवरात्रि में परिवार का एक सदस्य जजमान बनकर पूजा करता है। आस्था से जुड़ी मान्यताएं - ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव में अकाल या महामारी के समय माता की आकाशवाणी होती थी और माता की कृपा से गांव की रक्षा होती थी। आज भी श्रद्धालु लोट मारते हुए माता के दरबार पहुंचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था के कारण दूर-दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं।

विश्व शांति और सुख समृद्धि के लिए कराई जाती हैं पूजा - हर नवरात्र में ट्रस्ट की ओर से विश्व शांति सुख समृद्धि मनोकामना पूर्ण करने के लिए विधि विधान से देवी पाठ और अभिषेक कराया जाता हैं,तिवारी परिवार की कुल देवी माना जाता हैं और जजमान के रूप में तिवारी परिवार के एक सदस्य को पूजा में बैठाया जाता हैं, यहां की देवी को मन की सुनने वाली मां मानकादाई कहते हैं। हजारों ज्योति कलश, दूर-दराज से पहुंचते हैं श्रद्धालु - नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु मां मानकादाई के दर्शन के लिए आते हैं। यहां चार हजार से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए जा रहे हैं। श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना लेकर माता के दरबार में मत्था टेकते हैं।

नौ दिनों तक लगता है विशाल मेला - मंदिर के पास तालाब किनारे नौ दिनों तक भव्य मेला लगता है। जिले के अलग-अलग गांवों से लोग यहां पहुंचकर मेला का आनंद उठाते हैं। मंदिर परिसर, तालाब और आसपास का प्राकृतिक वातावरण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था - मां मानकादाई पब्लिक ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि के नौ दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। हर दिन हजारों भक्त दर्शन के बाद प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। देवी-देवताओं से घिरा है खोखरा गांव - खोखरा गांव में कई देवी-देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। इनमें मुख्य रूप से मां मानकादाई, शारदा देवी, काली माता, शीतला माता, ठाकुर देवता, पराउ बैगा, प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और धोबनीन दाई शामिल हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में 200 से अधिक तालाब भी मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की विशेष पहचान हैं। ऐसे पहुंचे मां मानकादाई मंदिर - मां मानकादाई मंदिर जांजगीर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर खोखरा गांव में स्थित है। नैला रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। बिलासपुर से लगभग 50 किलोमीटर और रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर यह आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

सालियापारा की समस्याओं पर उठी आवाज: मूलभूत सुविधाओं के सुधार की मांग, प्रशासन से समाधान की उम्मीद

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-कांकेर बरदेवरी क्षेत्र के सालियापारा में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों में असंतोष देखा जा रहा है। मूक पत्रिका की टीम द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरे के दौरान गांव की विभिन्न समस्याएं सामने आईं, जिनमें सड़क, स्ट्रीट लाइट और तालाब की खराब स्थिति प्रमुख रूप से शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि आवागमन के लिए लोगों को मजबूरी में जंगल और पहाड़ी रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। इन रास्तों पर जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं, लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और जर्जर तालाब की स्थिति से भी ग्रामीण परेशान हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि गांव में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र तक उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके पोषण और प्रारंभिक शिक्षा पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। मूक पत्रिका टीम द्वारा इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द समाधान की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि समय पर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, तो वे आगे उचित कदम उठाने को बाध्य होंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा, ताकि गांव में मूलभूत सुविधाएं बेहतर हो सकें और जनजीवन सुचारू रूप से चल सके।

सारंगढ़ जिला अस्पताल में 'जहर' परोस रहा प्रशासन! वाटर कूलर में मिली मरी हुई छिपकली

सारंगढ़/मूक पत्रिका

क्या आप जानते हैं कि जिस अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं, वहीं से आपको नई बीमारियां मिल सकती हैं? छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहाँ शहर पहले से ही पीलिया की चपेट में है, वहीं जिला अस्पताल के वाटर कूलर में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया है।÷सारंगढ़ शहर इन दिनों दूषित पानी और पीलिया के बढ़ते प्रकोप से जूझ रहा है।

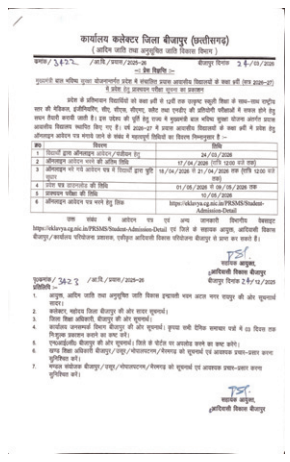

लेकिन प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि खुद जिला चिकित्सालय भी सुरक्षित नहीं रहा। आज ह्रस्ढ्ढ के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा जब अस्पताल परिसर में पानी पीने पहुंचे, तो वाटर कूलर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। वाटर कूलर के भीतर एक मरी हुई छिपकली तैर रही थी। स्वच्छ जल÷ के बिना ÷स्वच्छ कल÷ की कल्पना बेमानी है। एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान के नारे लगाती है, तो दूसरी तरफजिला अस्पताल जैसी संवेदनशील जगहों पर ऐसी जानलेवा लापरवाही देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद प्रशासन जागता है या शहर को इसी तरह दूषित पानी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा।

मेधावी छात्रों को मुफ्त आवासीय शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मौका

प्रयास नवमी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

बीजापुर/मूक पत्रिका

कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
-: प्रेस विज्ञप्ति :-

जिले के आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए सत्र 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत चल रही इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मौका देना है।जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक छात्र 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 17 अप्रैल 2026 रात 12 बजे तक तय की गई है। आवेदन में सुधार के लिए 18 से 21 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले छात्र 1 मई से 9 मई तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए और सीएस जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विशेष तैयारी भी कराई जाएगी। यहां से करें आवेदन छात्र ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/student -Admission-Detail पर जा सकते हैं। इसके अलावा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय बीजापुर या एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है।

जनकल्याणकारी योजनाओं से संवर रहा तनीषा का भविष्य

बास्तानार के श्रमिक किरण ठाकुर की प्रेरक कहानी

बास्तानार/मूक पत्रिका

ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की अलख जगाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल देने की शासन की मंशा अब धरातल पर रंग लाती दिख रही है। विकासखण्ड बास्तानार के ग्राम तुरांगुर निवासी किरण ठाकुर की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ सरकारी सहायता ने एक पिता के अपनी बेटी को पढ़ाने के संकल्प को नई उड़ान दी है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत किरण ठाकुर अपनी सुपुत्री तनीषा ठाकुर को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत थे, जो वर्तमान में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है। इसी दौरान उन्हें अपने एक मित्र के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। शिक्षा के प्रति जागरूक किरण ने बिना देर किए आवश्यक दस्तावेजों के साथ श्रम संसाधन केंद्र में आवेदन किया, जिसके सुखद परिणाम जल्द ही सामने आए। डीबीटी के माध्यम से किरण ठाकुर के बैंक खाते में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इतना ही नहीं, उन्हें निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना का भी लाभ मिला, जिसके तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई। कुल 5,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता ने तनीषा की पढ़ाई की राह में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर कर दिया है।

रयास नवमी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, मेधावी छात्रों को मुफ्त आवासीय शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मौका

बीजापुर/मूक पत्रिका

कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
-: प्रेस विज्ञप्ति :-

जिले के आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए सत्र 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत चल रही इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मौका देना है।जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक छात्र 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 17 अप्रैल 2026 रात 12 बजे तक तय की गई है। आवेदन में सुधार के लिए 18 से 21 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले छात्र 1 मई से 9 मई तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए और सीएस जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विशेष तैयारी भी कराई जाएगी। यहां से करें आवेदन छात्र ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/student -Admission-Detail पर जा सकते हैं। इसके अलावा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय बीजापुर या एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है।

शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा: छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर से की शिकायत..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन के दौरान ग्राम टिमरलगा, हिच्छा और औराचक्का के सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब दुकान के खिलाफ आवाज उठाई। ग्रामीणों ने टिमरलगा (हिच्छाङ्कऔराचक्का मार्ग) पर संचालित शासकीय मदिरा दुकान को बंद करने या कहीं और शिफ्ट करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से रोज बड़ी संख्या में छात्राएं स्कूल और कॉलेज जाती हैं, लेकिन शराब दुकान के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे छात्राओं को छेड़छाड़, पीछा करने और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्राएं डर के कारण स्कूल जाना भी छोड़ने लगी हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। महिलाओं ने भी अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि इसी रास्ते से वे खेत और काम पर जाती हैं, लेकिन शराबियों के कारण उनका निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन गाली-गलौज और गलत हरकतें होती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान पर खतरा बना हुआ है। किसानों ने बताया कि शराब पीने वाले लोग खेतों में बोतलें फेंक देते हैं, जिससे काम करते समय चोट लगने का डर रहता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस मामले में पंचायत में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब सभी ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द कार्रवाई कर इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि इलाके में सुरक्षित माहौल बन सके।

पेज1 और सतरंगी मीडिया पी.आर सर्विसेज की सी.ई.ओ और फिल्म निर्मात्री सुशीला जीत साहनी जी ने उत्तर भारतीय और भारतवर्ष के सभी श्रद्धालुओं को चैत्र छठ पूजा की दी ढेरों शुभकामनाएं।

जित मुम्बई/मूक पत्रिका

हिन्दी फिल्म इंडस्ट्रीज कि जानी-मानी फिल्म निर्मात्री एवम फिल्म प्रचारक सुशीलाजीत साहनी ने चार दिवसीय का महाअनुष्ठान चैत्र शुक्ल पक्ष छठ महापर्व के लिए तमाम उत्तर भारतीय और भारतवर्ष के सभी श्रद्धालुओं को चैत्र छठ पूजा की दी ढेरों शुभकामनाएं दी। सुशीलाजीत का मानना है की मैं एक मराठी परिवार से ताल्लुकात रखती हैं लेकिन मेरी ससुराल बिहार के पटना जिले स्थित है। मेरी सासु मां अश्विन मास की छठ करती हैं लेकिन काम के कारण मैं आज तक पूजा में शामिल नहीं हो पाई । सुशीलाजीत ने यह भी बताया की यह पर्व मेरे लिए बहुत ही खास महत्व रखता है।आगे उन्होंने बताया की छठ पूजा सूर्य देव और प्रकृति (जल, वायु) की उपासना का एक चार दिवसीय (नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य) कठिन महापर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व कठोर स्वच्छता, 36 घंटे के निर्जला उपवास, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने और निःस्वार्थ आस्था के लिए जाना जाता है।

छठ पूजा की मुख्य विशेषताएं:- प्राकृतिक पूजा: इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, बल्कि जल, सूर्य और प्रकृति की पूजा की जाती है। यह पर्यावरण के अनुकूल त्यौहार है।

- अर्घ्य परंपरा: डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन और निरंतरता का प्रतीक है।

- कठोर तपस्या: व्रती 36 घंटे तक बिना पानी पिए (निर्जला) उपवास रखते हैं, जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है।

- सादा और पवित्र भोजन: प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल, और मौसमी फल मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाए जाते हैं, जो सादगी और शुद्धता को दर्शाता है।

- सामाजिक समानता: इस पर्व में जाति-भेद नहीं होता; सभी एक साथ मिलकर नदी या तालाब के किनारे अर्घ्य देते हैं।- वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ: सूर्य पूजा और पानी में लंबी अवधि तक खड़े रहने से विटामिन ष्ठ मिलता है और त्वचा रोगों में लाभ मिलता है, साथ ही यह पर्व स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से छठी मैया (सूर्य देव की बहन) को समर्पित है, जो बच्चों की रक्षा और परिवार की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

प्राचार्यों की बैठक में शिक्षा सुधार, FLN मिशन और नई कार्ययोजना पर विशेष जोर

शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन सर्वोपरि संयुक्त संचालक एच. आर. सोम का कांकेर दौरा

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-कांकेर 24 मार्च 2026 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, बस्तर संभाग एच. आर. सोम के कांकेर प्रवास के दौरान जिले की शिक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के पश्चात सोम जी ने पीएम श्री शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने विद्यालय में संचालित विभिन्न प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।शिक्षकों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने शिक्षण पद्धति, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने परविस्तार से चर्चा की। उन्होंने निपुण भारत मिशन के तहत आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता (स्नस्ह्र) को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों को लक्ष्य आधारित कार्य करने के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने पीएम श्री विद्यालयों में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने तथा उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अनुशासित वातावरण ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव होता है। साथ ही सोम जी ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया और मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरे के दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में विकासखंड कांकेर, नरहरपुर एवं चारामा के खंड शिक्षा अधिकारियों, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों तथा संकुल समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं के सुचारू संचालन, स्नस्ह्र मूल्यांकन की प्रगति, आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कार्ययोजना एवं लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके अलावा विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं-भवन, पेयजल, शौचालय एवं बिजली-की उपलब्धता सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवाचार अपनाने, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने और परीक्षा परिणामों में सुधार लाने के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान समर कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि विद्यार्थियों का सतत शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद एवं डीएमसी नवनीत पटेल, प्राचार्य रचना श्रीवास्तव सहित संबंधित विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारी, सभी प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर, संयुक्त संचालक का यह दौरा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, गुणवत्ता सुधार और अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण और नवीन आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च

12वी से उच्चतर पढ़ाई कर रहे एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को जमा करना होगा ऑनलाइन आवेदन

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि, वे शिक्षा सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति के लिए विभागीय पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन https://postmatric-scholarship.cg.nic.in में नवीनीकरण और नवीन आवेदन 27 मार्च 2026 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद शिक्षा सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति के लिए विभागीय पोर्टल को बंद किया जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु पात्रताअनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय सीमा 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम संलग्न करना होगा। पीएफ्रूमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय कोसीर रोड कालेज के पास सारंगढ़ से प्राप्त की जा सकती है।

संपादकीय

सिस्टम का 'शॉर्ट सर्किट' और खराब उपकरण बन रहे मौत का कारण ?

दिल्ली में अनियोजित विकास की आपाधापी में जिस तरह से नियमों को धता बताया जाता रहा है, उसका नतीजा बार-बार किसी हृदयविदारक हादसे के रूप में सामने आता है। राजधानी के पालम इलाके की एक रिहाइशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग बच गए, लेकिन बुरी तरह झुलसे हैं।बताया जा रहा है कि घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। उस इमारत में भूतल और पहली मंजिल पर कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें थीं, जिससे आग मिनटों में फैली। घर की बनावट ऐसी थी कि फंसे लोगों को बचाने की कोशिश नाकाम रही। साथ ही, मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों के खराब उपकरणों के कारण बचाव कार्य में देरी हुई।अगर विभाग की हाइड्रोलिक प्रणाली समय पर काम करती, तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस अग्निकांड से कई पुराने सवाल उठ रहे हैं, जिन पर अक्सर चर्चा होती है और नतीजा सिफर रहता है। इस हादसे में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और विफलता के सवाल अहम हैं। दिल्ली में ऐसी कई इमारतें हैं, जो मिश्रित आवासीय-व्यावसायिक हैं। अवैध कालोनियों में नियमों के अनुपालन की उम्मीद करना बेमानी है।राजधानी में अधिकांश जगहों की यही तस्वीर है। ऐसी जगहों पर किसी भी तरह का हादसा होने पर बचाव कार्य में प्राय-दिक्कत होती है। संकरी गलियों के कारण आग लगने पर दमकल गाड़ियां पहुंचने में समय लेती हैं। अनियोजित बस्तियों में आपातकालीन सेवाओं के प्रभावी ढंग से काम करने की अक्षमता कई बार उजागर हुई है। पालम में भी यह स्थिति दिखी।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस तरह के इलाकों में आग लगने की घटनाओं की कई बार भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दो साल पहले विवेक विहार के एक अस्पताल में आग लगने से आठ शिशुओं की मौत हो गई थी। ऐसी सैकड़ों घटनाएं दर्ज की गई हैं। अक्सर, इमारतों में अग्नि सुरक्षा संबंधी इंतजाम नहीं होते। विद्युत प्रणालियां दोषपूर्ण होती हैं या भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है।ऐसे हादसों में अक्सर प्रशासनिक उदासीनता, नगर निकायों में भ्रष्टाचार और विकासकर्ताओं तथा अधिकारियों के बीच सांठगांठ के तथ्य सामने आते हैं। सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो? अधिकारियों को चाहिए कि वे आपदाओं के बाद नोटिस जारी करने से आगे बढ़कर सभी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।दिल्ली में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए, संकरी गलियों में अग्निशमन सेवाओं की पहुंच में सुधार और विद्युत अवसंरचना का उन्नयन आवश्यक है।

56 इस्लामिक देशों को मिलाकर गठित ओआईसी और उसके इस्लामिक नाटो बनाने का वैश्विक लक्ष्य, यहूदियों के एकमात्र छोटे से मुल्क इजराइल को समाप्त करने पर तुले हुए ईरान की सनक से गहराते फिलिस्तीन-गाजा विवाद और भारतीय हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान परस्त ओआईसी के अंतर्राष्ट्रीय दांवपेंचों ने जब हिंसक और आतंकवाद परस्त इस्लामिक दुनिया को मौजूदा क्रूर संघर्ष के मुकाम तक पहुंचा दिया तो जिधर देखें उधर तबाही और बर्बाद होने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। वैचारिक सवाल है कि जब हर हिंसक सोच का त्रासदीपूर्ण अंत होना नैसर्गिक प्रक्रिया के मुताबिक तय है तो फिर ईरान और अमेरिका इसी रक्तिम राह पर अग्रसर क्यों हैं? और यदि वो ऐसे ही हैं तो इससे शेष दुनिया आश्चर्यचकित क्यों है? शायद इसलिए कि उनके तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो चुकी है।

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध से तेल-गैस संकट गहराया

(कमलेश पांडे)

दिलचस्प बात तो यह है कि गैर नाटो देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत ने भी इस मामले में अमेरिका के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया है। यूँ तो अमेरिका ने चीन से भी होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में सहयोग मांगा, लेकिन सबने इंकार कर दिया, जिससे अमेरिका अलग थलग पड़ गया।

पश्चिमी एशिया के लिए अभिशाप साबित हो रहे ईरान-इजरायल युद्ध, कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि एक प्रकार का सभ्यता-संस्कृति संघर्ष है, जिसके बीज इतिहास में ही जमे हुए हैं। एक ओर जहां यह युद्ध इजरायल के लिए उसके अस्तित्व के रक्षा की लड़ाई है, वहीं दूसरी ओर यह युद्ध ईरान के लिए ईसाई मुल्कों के कथित लोकतांत्रिक-आर्थिक दांवपेंचों से ईरान को महफ़ूज रखकर अरब-खाड़ी देशों में एक मजबूत इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने की मन-संकल्पित सोच-समझ और ईरान से वैश्विक इस्लामिक साम्राज्यवाद का दबदबा बढ़ाने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर लड़ी जा रही है, जो आगे भी बदस्तूर जारी रह सकती, क्योंकि ईरानी धार्मिक शासन व संगठन का एकमात्र ध्येय यही है।

वहीं, पश्चिम एशिया और मध्य-पूर्व के अकूत तेल व गैस भंडार पर जिस तरह से अमेरिकी-यूरोपीय गठबंधन वर्चस्व कायम है, और अपने अपने हितों को लेकर उनके बीच भी अंतर्विरोध उपज चुका है, वह अप्रत्याशित है। जबकि मध्यपूर्व में अमेरिकी वर्चस्व तोड़ने के लिए रूसी-चीनी नेतृत्व भी आमादा प्रतीत हो रहे हैं, जिसके दृष्टिगत चल रहे दांवपेंचों से इस्लामिक मुल्क लगभग दो या चार फाड़ हो चुके हैं। सच कहूं तो शिया-सुन्नी इस्लामिक विभाजन इसकी जड़ में है, लेकिन सुन्नी बहुल सऊदी अरब, शिया बहुल ईरान, हिन्दू विरोधी पाकिस्तान और मुसलमानों का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्किये के आपसी दांवपेंच किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

इसके बावजूद, 56 इस्लामिक देशों को मिलाकर गठित ओआईसी और उसके इस्लामिक नाटो बनाने का वैश्विक लक्ष्य, यहूदियों के एकमात्र छोटे से मुल्क इजराइल को समाप्त करने पर तुले हुए ईरान की सनक से गहराते फिलिस्तीन-गाजा विवाद और भारतीय हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान परस्त ओआईसी के अंतर्राष्ट्रीय दांवपेंचों ने जब हिंसक और आतंकवाद परस्त इस्लामिक दुनिया को मौजूदा क्रूर संघर्ष के मुकाम तक पहुंचा दिया तो जिधर देखें उधर तबाही और बर्बाद होने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता।

वैचारिक सवाल है कि जब हर हिंसक सोच का त्रासदीपूर्ण अंत होना नैसर्गिक प्रक्रिया के मुताबिक तय है तो फिर ईरान और अमेरिका इसी रक्तिम राह पर अग्रसर क्यों हैं? और यदि वो ऐसे ही हैं तो इससे शेष दुनिया आश्चर्यचकित क्यों है? शायद इसलिए कि उनके तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो चुकी है, और अबतक सारा शांतिपूर्वक तमाशा देखने वाला खेल लगभग बिगड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक दायित्व पर सवालिया निशान तो बहुत पहले ही लग चुके हैं, लेकिन पीस बोर्ड ऑफ गाजा क्या कर रहा है?

उधर, अमेरिकी-यूरोपीय देशों को बैलेंस रखने वाले रूस-चीन-उत्तरकोरिया गठजोड़ और अमेरिका को छोड़कर वीटो शक्ति प्राप्त अन्य चार देश क्या कर रहे हैं? दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला भारत और उसका ग्लोबल साउथ चुप्पी क्यों साधे बैठें हैं? कथित ओआईसी ईरान को मरता-पिछड़ता देखकर बेचैन क्यों नहीं हो रहा है? अब्राहम परिवार के भागीदार देशों के मुंह पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? यदि कुछ देशों को परमाणु बम रखने और लंबी दूरी वाली मिसाइल बनाने का हक है तो फिर वही हक ईरान को रहने देने में किसको परेशानी हुई है?

सुलगता सवाल है कि क्या कर ईरान को परमाणु बम बनाने का हक नहीं है, जबकि सिर्फ पाकिस्तान को यही हक अमेरिकी अगुवाई में प्राप्त है? क्या ईरान को लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का हक नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान को अमेरिकी-चीनी सरपरस्ती में प्राप्त है? आखिर ऐसी ओछी दलीलों के पीछे अमेरिकी खलनीति तो साफ नजर आती है, क्योंकि इन्हीं सतही वजहों के सहारे ईरान पर हमले किए गए। न केवल ईरानी सुप्रीम

लीडर और उनके चहेतों को मार गिराया गया, बल्कि उच्च पदस्थ लोगों के खात्मे का सिलसिलेवार अभियान इजरायल द्वारा जारी है!

फिर भी ईरान ने जो अपनी रणनीतिक ताकत दिखाई, संगठनात्मक क्षमता प्रदर्शित किया, उससे ईरान विरोधी देश दंग हैं और यूरोपीय नाटो देश भयभीत! शायद इसलिए भी अब वो अमेरिका के साथ पूरी तरह से खड़े दिखाई देना नहीं चाहते हैं। ईरान अपने ही सहोदर अरब-खाड़ी व मध्यपूर्व के देशों की जो कुटाई कर रहा है, उसकी कल्पना भी कभी ओआईसी ने नहीं की होगी! इन तमाम रक्तिम रंजिशों के पीछे समझदारी की भावना है या ईर्ष्या का भाव, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ईरान क्या करेगा? अमेरिका इजरायल परस्त अपने पड़ोसियों को कितना बर्बाद कर पाएगा, यह वक्त बताएगा।

सवाल यह भी है कि जब इस्लामिक नाटो बनाने के सपने संजोए जा रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क भारत विरोध के नाम पर इजरायल विरोध तक पर तुले हुए हैं, उसके दृष्टिगत इजरायल का आक्रामक होना लाजिमी है। इस लंबे खिंचते जा रहे युद्ध से बचने के लिए दुनिया के थानेदार अमेरिका ने पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी एशिया में ईरान अपनी मनमानी पर तुला हुआ है, उसे रूस-चीन-उत्तरकोरिया और कुछ हदतक भारत का समर्थन हासिल है, उसके दृष्टिगत इजरायल की रक्षा करने का कर्तव्य अमेरिका का तो बनता ही है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहूदी कौम ही है। वो भी तब जबकि पश्चिमी एशिया के सुन्नी मुस्लिम देश भी शिया मुस्लिम मुल्क ईरान को कमजोर रखने को लालायित हों।

यही वजह है कि अमेरिकी आक्रामकता, इजरायली वीरता, भारतीय तटस्थता और रूस-चीन की किंकर्तव्यविमूढ़ता जहां ईरान की फजीहत करवा रही हैं, वहीं शेष दुनिया में तेल-गैस के लाले पड़े हुए हैं। इससे इनके दाम आसमान छू रहे हैं। इसी बीच होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर अमेरिकी प्रस्ताव से इतर नाटो में उभरे मतभेद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण के गहरे अंतर को दर्शाने को काफी हैं। इससे तेल-गैस के संकट गहराने और महंगाई बढ़ने के आसार प्रबल हैं।

इस स्थिति से बचने हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सदस्यों से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की मांग की है, लेकिन यूके और जर्मनी जैसे देशों ने इसे नाटो का मामला मानने से इनकार कर दिया। इस मतभेद के कई कारण हैं। उल्लेखनीय है कि ईरान-अमेरिका-इज़राइल संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा ले जाता है। इससे विफरते हुए ट्रंफ ने चेतावनी दी कि सहयोगी मदद न करने पर नाटो का भविष्य 'बहुत बुरा' होगा, लेकिन जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने कहा कि नाटो ने कोई फैसला नहीं लिया और यह उसकी जिम्मेदारी नहीं। जबकि यूके के पीएम कीयर स्टार्मर ने यूरोप, खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ अलग गठबंधन बनाने की बात कही, नाटो को शामिल किए बिना।

दिलचस्प बात तो यह है कि गैर नाटो देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत ने भी इस मामले में अमेरिका के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया है। यूँ तो अमेरिका ने चीन से भी होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में सहयोग मांगा, लेकिन सबने इंकार कर दिया, जिससे अमेरिका अलग थलग पड़ गया। सवाल है कि जिस नाटो को अमेरिका ने खड़ा किया, आज वही अमेरिकी इशारे को मानने को तैयार क्यों नहीं हुआ? आखिर इसके क्या कूटनीतिक मायने हैं?

चूंकि ये मतभेद नाटो की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, खासकर मध्य पूर्व जैसे क्षेत्र में जहां अनुच्छेद 5 (सामूहिक रक्षा) लागू नहीं होता। दरअसल, यूरोपीय देश पश्चिम एशिया को नाटो के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं, जो ट्रंप की 'ट्रांजेक्शनल' नीति से टकरा रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो रहा है और ईरान को संकेत मिल रहा है कि नाटो विभाजित है। स्पष्टत-इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत के लिए, जो तेल आयात पर निर्भर है, यह ऊर्जा संकट बढ़ा सकता है।

ममता बनर्जी के किले में इस बार लग सकती है सेंध, भाजपा ने बिछाई है जबरदस्त चुनावी बिसात

(नीरज कुमार दुबे)

भाजपा ने सामाजिक समीकरणों पर भी खास ध्यान दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर पार्टी ने अपने आधार को और व्यापक बनाने का प्रयास किया है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण तक हर क्षेत्र में संतुलन साधने की रणनीति साफ दिख रही है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली और दूसरी सूची जारी कर साफ संकेत दे दिया है कि इस बार वह आधी अधूरी तैयारी के साथ नहीं बल्कि पूरी ताकत, पूरी रणनीति और पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरी है। खासतौर पर दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नामों पर नजर डालने पर पता चलता है कि एक एक सीट पर गहरे मंथन के बाद उम्मीदवार तय किये गये हैं। हम आपको बता दें कि हिंगलगंज से रेखा पात्रा, खड़दह से कल्याण चक्रवर्ती, सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, मथाभांगा से निसिथ प्रमाणिक, चोपड़ा से शंकर अधिकारी, बैरकपुर से कौस्तव बागची, कमरहाटी से अरूप चौधरी जैसे नाम सीधे चुनावी मुकाबले को और दमदार बना रहे हैं। इसके अलावा एंटाली से प्रियंका तिबरेवाल और मणिकतला से तपस रॉय जैसे उम्मीदवार राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं।

अगर पहली सूची पर नजर डालें तो वहां भी बड़े नामों की भरमार है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर से उतारकर पार्टी ने सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे दी है। दिलीप घोष, स्वपन दासगुप्ता, अग्निमित्रा पाल, रुद्रनील घोष और बंकिम चंद्र घोष जैसे चेहरे इस चुनाव को हाई वोल्टेज बना रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार पार्टी ने सिर्फ चर्चित चेहरों पर नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा दिखाया है। आउसग्राम से कलिता माजी जैसी साधारण पृष्ठभूमि की कार्यकर्ता को टिकट देना इसी रणनीति का हिस्सा है।

इस चुनाव का एक और बड़ा और चौंकाने वाला पहलू है पूर्व पुलिस आयुक्त डॉ. राजेश कुमार का राजनीति में प्रवेश। यह सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम नहीं बल्कि भाजपा की रणनीतिक चाल है। डॉ. राजेश कुमार का प्रशासनिक अनुभव, वित्त और प्रबंधन में गहरी समझ और कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ उन्हें एक अलग ही स्तर का नेता बनाती है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल, अपराध जांच विभाग और यातायात सुरक्षा जैसे अहम पदों पर उनकी भूमिका उन्हें आम नेता से अलग पहचान देती है।

उनकी छवि एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी की रही है। मानव तस्करी के खिलाफ उनकी मुहिम और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए किए गए काम उन्हें जनता के बीच भरोसेमंद चेहरा बनाते हैं। भाजपा के लिए यह कदम इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में एक पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी का चुनावी मैदान में उतरना सीधे तौर पर संदेश देता है कि पार्टी व्यवस्था सुधारने के लिए गंभीर है।

राजनीतिक रूप से भी यह दांव गहरा है। डॉ. राजेश कुमार का प्रशासनिक और बौद्धिक कद भाजपा को उस वर्ग में भी मजबूती देगा जो अब तक तटस्थ रहा है। उनकी कानूनी लड़ाइयों ने यह भी साबित किया है कि वह दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। यह छवि भाजपा के लिए चुनाव में बड़ी पूंजी साबित हो सकती है।

इस चुनाव को और भावनात्मक और विस्फोटक बनाने वाला मुद्दा है आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना। उस दर्दनाक घटना ने पूरे बंगाल को झकझोर दिया था। अब पीड़िता की मां का राजनीति में आने का संकेत यह बता रहा है कि जनता के भीतर गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। महिलाओं का सड़क पर उतरना, रात भर प्रदर्शन करना और न्याय की मांग करना तृणमूल सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनमत बना चुका है। माना जा रहा है कि पीड़िता की मां ने भाजपा से पनिहाटी से टिकट मांगा है। भाजपा उन्हें उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि पार्टी उस जनाक्रोश को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि पनिहाटी उन 38 सीटों में शामिल है जहां से भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किये हैं।

आपातकाल में गए जेल फिर बने पत्रकारिता की आवाज, मिसाल है सतीश जैन की जीवन यात्रा

करेली / 25 जून 1975...भारत के इतिहास का वो काला दिन जो आज भी देश की शान पर बदनुमा दाग की तरह है. इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी (आपातकाल) की घोषणा कर दी थी. आपातकाल से मतलब है लोगों के अधिकार खत्म और सिर्फ अंधा कानून. संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया था. जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता उसे जेल में ठूंस दिया जाता था. जब देश भर की जेलें राजनैतिक कैदियों से भर गई तो सरकारी इमारतों को अस्थाई जेल बनाकर आपातकाल के विरोधियों को उसमें रखा गया.

इस सबके बीच सुकून की सिर्फ एक वजह, एक आस थी...वो थे देश के युवा. जिन्होंने ठान लिया था कि इस तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे. उन्होंने जान की बाजी लगाकर आपातकाल का विरोध किया. फिर चाहे वो गांव हो या शहर हर जगह एक ही नारा था इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, यहां के संविधान को बचाना है.

देश के दिल से उठी विरोध की आवाज... : देश के दिल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के छोटे से कस्बे करेली के युवा भी इससे इतर नहीं थे. उन्होंने भी जैसे ही आपातकाल की घोषणा सुनी, इसके विरोध में नगर के मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला. जमकर नारेबाजी की, जिनमें से कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इससे आंदोलनकारियों को यह समझ आया कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है. तब उन्होंने भी इसके लिए कमर कस ली. जबकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलना भी बहुत मुश्किल होता था. लोग डरते थे.

नारे लिखने पर भेजा गया जेल : इन युवाओं में 22 साल के युवा पत्रकार सतीश जैन भी शामिल थे. वे अपने 2 अन्य साथियों विजय सोनी और रशीद कुरैशी के साथ रात में नगर के प्रमुख स्थलों और पुलिस थाने की दीवारों पर आपातकाल के विरोध में नारे लिखा करते थे, ताकि लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरुक कर सकें. लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आया.

एक सुबह कांग्रेस के नेताओं ने युवा पत्रकार सतीश जैन को पुलिस से गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया. इसके बाद वे कई महीनों तक जेल में रहे. लेकिन कांग्रेस की तानाशाही के आगे सिर नहीं झुकाया. पूरे देश में कड़े विरोध के बाद आखिरकार इंदिरा गांधी को इमरजेंसी हटानी पड़ी.

पत्रकारिता के क्षेत्र में बने मिसाल : जेल से आने के बाद युवा पत्रकार सतीश जैन ने सामाजिक कार्यों को अपने जीवन का मकसद बना लिया. एक ओर वे अपनी लेखनी के जरिए युगधर्म, स्वदेश नवभारत, दैनिक भास्कर, देशबंधु जैसे कई अखबारों में नगर से जुड़े मुद्दे उठाते रहे. ईमानदारी और बड़ी मेहनत से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जिले में अपनी अलग पहचान बनाई. तहसील पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहकर जिले के पत्रकारों को भी नई दिशा दी. कई पत्रकार सम्मेलन और साहित्य सम्मेलनों में हिस्सा लिया और आयोजन में सहयोग किया.

सामाजिक कार्यों में भी सक्रियता : सतीश जैन ने पत्रकारिता के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी पूरी सक्रियता से योगदान दिया. नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था नव जाग्रति मंडल के सदस्य बने और सस्वती शिशु मंदिर के संचालन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई.

इस दौरान वे अपनी कलम के जरिए विभिन्न अखबारों में नगरवासियों की सुविधाओं के लिए सरकार से मांग उठाते रहे, साथ ही विभिन्न आंदोलनों और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे. धार्मिक आयोजन जैसे गणेश उत्सव हो या नगर के युवाओं की शिक्षा के लिए सुभाष वाचनालय की शुरुआत करना और उसका सुव्यवस्थित संचालन करना. या फिर नगर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 20 बिस्तर के अस्पताल की मांग को लेकर धरना देना, मेल ट्रेन के करेली स्टॉपेज के लिए रेल रोको आंदोलन करना, घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति के लिए आंदोलन करना... सभी में पत्रकार सतीश जैन ने सक्रियता से भूमिका निभाई.

यही वजह है कि बीते करीब 40 सालों की पत्रकारिता की लंबी यात्रा में उन्होंने ना केवल करेली नगर बल्कि पूरे नरसिंहपुर जिले में अपनी अमिट छाप छोड़ी. कई सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें इन कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे लोगों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देकर सम्मानित किया, जिसमें सतीश जैन भी शामिल हैं. आज उनकी पत्रकारिता की विरासत को उनकी बेटी श्रद्धा जैन आगे बढ़ा रही है. जिसने देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों और टीवी चैनल के लिए रिपोर्टिंग की. वर्तमान में श्रद्धा जैन देश के टॉप न्यूज चैनल जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं.

जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ पूर्ण करें : कलेक्टर सुश्री ममगाई

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की लंबित प्रकरणों की समीक्षा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दी। उन्होंने जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ पूर्ण करने निर्देशित की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसे सभी संबंधित अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का खाका तैयार होता है। अतः डेटा प्रविष्टि और गणना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले प्रगणकों को आम नागरिकों से जानकारी लेते समय अत्यंत विनम्र और संवेदनशील रहने कहा है। जिसमें सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।

सौंपे गए लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के कड़े निर्देश-कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सौंपे गए लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने ''समय-सीमा'' की बैठक में इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने की बात कही है।

कलेक्टर ने कहा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर विलंब या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।जल संरक्षण ,संवर्धन एवं संग्रहण महत्वपूर्ण, सभी ग्राम पंचायत, इस दिशा में ''सोख्ता गड्ढा'' और ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' पर करें प्रभावी कार्यवाही कलेक्टर ने जल संरक्षण, संवर्धन एवं संग्रहण के लिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ''सोख्ता गड्ढा'' और ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दी है। कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्म ऋतु और गिरते भू-जल स्तर को देखते जिले के सभी विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण की दिशा में सोख्ता गड्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रभावी कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों के शासकीय भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत सचिवालयों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएं। इसी तरह हैंडपंपों और सार्वजनिक नलों के पास व्यर्थ बहने वाले पानी के संचयन के लिए वैज्ञानिक पद्धति से सोख्ता गड्ढों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि भू-जल स्तर में सुधार हो सके। कलेक्टर ने मनरेगा का अभिसरण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 15वें वित्त आयोग के तालमेल से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जन-भागीदारी से ग्रामीणों को जल की महत्ता समझाने अभियान चलाएं-कलेक्टर ने जन-भागीदारी से ग्रामीणों को जल की महत्ता समझाने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूक करने कहा। जिससे वे अपने निजी घरों में भी जल संचयन की तकनीक अपनाएं। बैठक के दौरान सभी जनपद सीईओ और तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन संरचनाओं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो। कलेक्टर ने चेतावनी दी है, कि जल संरक्षण के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जाएगी।

सरसीवा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध हुई कार्यवाही

बेमेतरा/मूक पत्रिका

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 24 मार्च 2026/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर कोटपा दल ने सरसीवा क्षेत्र में संचालित 10 पान ठेला, गुमटियों, किराना दुकान होटलों, रेस्टोरेंट में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 का उल्लंघन करते पाए जाने पर क्रमश 1550 रूपये राशि का चालानी कार्यवाही किया। जांच टीम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक नीलिमा, कौशल साहू एवं पुलिस आरक्षक शामिल थे।

प्रति बुधवार को होगा मेडिकल बोर्ड की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में प्रति बुधवार को मेडिकल बोर्ड की बैठक और दिव्यांग शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा, जिसमें सभी किस्म के दिव्यांग सहित अन्य मरीज अपना सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं।

पापा राव समेत 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण 7 महिला कैडर शामिल, च-47 समेत हथियार सौंपेंगे

बीजापुर/मूक पत्रिका

बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के बीच मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लंबे समय से सक्रिय नक्सली कमांडर और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (छ्यर्स्ष्ट) के सदस्य व साउथ सब ज़ोनल ब्यूरो के इंचार्ज पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस खबर के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई। समूह में छ्ड्क्ष्टरू स्तर के प्रकाश मड़वी और अनिल ताती जैसे सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं। कुल 18 कैडरों में 7 महिला नक्सली हैं।अधिकारियों के अनुसार, सभी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने की इच्छा जताई है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत ये लोग,च-47 राइफल सहित अन्य हथियार भी सौंपेंगे।उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस घटनाक्रम को बड़ा मोड़ बताते हुए कहा कि पापा राव के आत्मसमर्पण के बाद प्रदेश में सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक स्थिति बन रही है।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण से पहले उनकी पापा राव से मोबाइल पर बातचीत भी हुई थी, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है।सुरक्षा एजेंसियां इस आत्मसमर्पण को दंडकारण्य क्षेत्र में माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका मान रही हैं। जिन कैडरों ने सरेंडर किया है, वे संगठन के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ऐसे में माना जा रहा है कि नक्सली नेटवर्क पर इसका सीधा असर पड़ेगा और नेतृत्व कमजोर होगा।प्रशासन का कहना है कि लगातार चल रहे अभियानों और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। इसे नक्सल-मुक्त बस्तर की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि जंगलों में सक्रिय बाकी कैडर भी जल्द ही शांति का रास्ता अपनाकर मुख्यधारा में लौटेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी 18 माओवादियों के पुनर्वास और पुनर्समावेशन की प्रक्रिया आगामी दिनों में पूरी की जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी।

विश्व क्षयरोग (टीबी) दिवस पर जिला चिकित्सालय बेमेतरा में कार्यक्रम आयोजित

100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ

बेमेतरा/मूक पत्रिका

विश्व क्षयरोग (टीबी) दिवस के अवसर पर बीते मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार तथा जिला क्षय अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय एमसीएच बेमेतरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में क्षयरोग (टीबी) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई।कार्यक्रम में जिला नगर अध्यक्ष विजय सिन्हा एवं वार्ड पार्षद की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर टीबी रोग के लक्षण, बचाव के उपाय, समय पर जांच और नियमित उपचार के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही टीबी के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने और मरीजों को समय पर इलाज के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम के दौरान 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ जिला नगर अध्यक्ष विजय सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से टीबी मरीजों की पहचान, समय पर जांच, उपचार और फॉलोअप पर विशेष जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य देश को टीबी मुक्त बनाने का है और इसके लिए जनसहभागिता बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर शहरी एवं ग्रामीण मितानिन, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (ह्ज्ञ्श्वक्क) से जुड़े सभी कर्मचारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी ली और लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। इस वर्ष विश्व क्षयरोग (टीबी) दिवस की थीम ÷हाँ! हम टीबी को समाप्त कर सकते हैंः देश के नेतृत्व में, लोगों द्वारा संचालित÷ रखी गई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच कराएं और समय पर उपचार लेकर टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने ली खनिज विभाग की समीक्षा बैठक, कलेक्टर ने संयुक्त टीम को लीज धारकों का खदान जॉच करने के निर्देश दिए

समस्त निर्माण विभाग और एजेंसी को रायल्टी चुकाने और रायल्टी जमा होने के बाद ही ठेकेदारों के बिल भुगतान के निर्देश

अनुपस्थित पट्टेदारों को कलेक्टर ने कारण बताओ पत्र जारी

कलेक्टर ने रेत घाटों में हो रहे अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण को रोक लगाने के दिए आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सारंगढ़ में खनिज विभाग के कार्यो का समीक्षा किया। बैठक में जिले के स्वीकृत खदान के प्रमुख पट्टेधारी अधिमानी बोलीदार, रेत एवं निर्माण विभाग और एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अनुपस्थित पट्टेदारों को कलेक्टर ने कारण बताओ पत्र जारी किये जाने निर्देशित किया। साथ ही राजस्व एवं खनिज की संयुक्त टीम को लीज धारकों का खदान जॉच करने निर्देशित किया। कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने जिले में स्वीकृ त गौण खनिज चूना पत्थर, डोलोमाईट के उत्खनी पट्टेधारियों को स्वीकृत पर्यावरण सम्मति एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान के मात्रा अनुसार, जो भी कम हो का रायल्टी 07 दिवस के भीतर शत प्रतिशत जमा करने एवं अग्रिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु अग्रिम रायल्टी जमा किया जाने निर्देशित किया। उन्होंने जिले के स्वीकृत नवीन रेत घाटों को शीघ्र प्रारंभ करने पर्यावरण स्वीकृति एवं कार्यालयीन कार्यो को पूर्ण कराने निर्देशित करते हुए रेत घाटों में हो रहे अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण को रोक लगाने आदेशित किया। कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने टिमरलगा एवं गुड़ेली क्षेत्र में स्थापित क्रेशरों क्षेत्रों जैसे जिले के स्वीकृत भण्डारण, क्रशरों को बड़े प्लांट के तर्ज पर बाउण्ड्रीवाल कराने और पौधा रोपण करने निर्देशित किया, जिससे क्रेशर से उड़ने वाले धूल कम हो सके। जिले के समस्त निर्माण, विभाग और एजेंसी जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपादित, प्रगतिरत सभी शासकीय निर्माण कार्यो में उपयोग किए खनिज की मात्रा एवं ठेकेदारों के द्वारा चल देयकों से काटकर रखी गई खनिज देय राशि 31 मार्च 2026 के पूर्व जमा कराने के लिए कलेक्टर ने सभी निर्माण अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही समस्त विभागों को रायल्टी चुकाने के निर्देश दिए और रायल्टी जमा होने के बाद ही ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किये जाने निर्देशित किया।बैठक में जानकारी दी गई कि, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले हेतु खनिज राजस्व से कुल 3550 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त लक्ष्य के विरूध्द अब तक लगभग राशि 2300 लाख ही राजस्व वसूली हो पाया है, जो निर्धारित लक्ष्य का केवल 64.78 प्रतिशत है। जिले के स्वीकृत गौण खनिज चूनापत्थर, डोलोमाईट के खदानों जिनकी पर्यावरण सहमति एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान के मात्रा अनुसार जो भी कम हो, में मात्रा निकासी हेतु शेष है। उल्लेखनीय है कि, सचिव खनिज साधन विभाग ने विगत सप्ताह में वीसी बैठक लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति, रेत खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन और निर्माण विभाग, एजेंसी द्वारा शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग किए जा रहे खनिज की मात्रा एवं ठेकेदारों के चल देयकों से काटकर रखी गई खनिज की देय राशि जमा कराने संबंधी निर्देश दिए।

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्रवाईः 12 ट्रैक्टर व 3 हाइवा जब्त

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु खनिज विभाग के उडनदस्ता दल द्वारा जिले के केवा, नवापारा, भादा, पुछेली, पिपरदा, बम्हनीडीह, केराकछार, खोरसी, देवरघटा, शिवरीनारायण आदि क्षेत्र में खनिजो के अवैध परिवहन, भण्डारण, उत्खनन करने वाले वाहनो व स्थानो का औचक जांच किया गया। खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान जिले में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते कुल 15 प्रकरण दर्ज कर जब्ती की कार्रवाई की गई है। जिसमें खनिज रेत अवैध परिवहन के 09 प्रकरण (06 ट्रेक्टर, 03 हाईवा), मिट्टी (ईंट) के 03 प्रकरण (03 ट्रेक्टर) तथा खनिज चूनापत्थर अवैध परिवहन के 03 प्रकरण (03 ट्रेक्टर) शामिल है। जप्त वाहनों को जिले के जांच क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना, शिवरीनारायण, पामगढ़, बिर्रा, पंतोरा तथा पुलिस लाईन जांजगीर में सुरक्षार्थ रखा गया है। खनिजो के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खांन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में खनिज विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही की जा रही है, जो कि आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।

236 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

नवागढ़ उपसंभाग में 'समाधान योजना 2026' के तहत विशेष शिविर आयोजित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत संभाग बेमेतरा के नवागढ़ उपसंभाग में ''समाधान योजना 2026'' के तहत विशेष शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत प्रदान करना और उन्हें योजना का लाभ दिलाना था।

5 वितरण केंद्रों में लगाए गए शिविर-नवागढ़ उपसंभाग के अधीन आने वाले 5 वितरण केंद्रों में एक साथ शिविर आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविरों के माध्यम से कुल 236 उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों में राहत पाने के लिए पंजीयन कराया, जिससे योजना के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता साफ दिखाई दी।

समीक्षा बैठक में बनाई गई आगे की रणनीति-शिविरों के सफल आयोजन के बाद कार्यपालन अभियंता श्री के.के. श्रीवास एवं सहायक अभियंता श्री डी.के. साहू ने नवागढ़ कार्यालय में मीटर रीडरों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में योजना का लाभ अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई।

गांव-गांव पहुंचकर किया जा रहा प्रचार-प्रसार-योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों ने स्वयं गांवों में जाकर प्रचार-प्रसार किया। ग्राम मुरता में सहायक अभियंता श्री नवीन कुमार वर्मा, चांदनू में कनिष्ठ अभियंता श्री मोहन दास बैरागी, गोधिकला में कनिष्ठ अभियंता श्री अनिल चंद्राकर, टेमरी में कनिष्ठ अभियंता श्री हरीश फरवी और ग्राम पुटपुरा में सहायक अभियंता श्रीमती पिंकी पांडेय ने उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजना के लाभों और नियमों की जानकारी दी।

डोर-टू-डोर अभियान से भी बढ़ा पंजीय-इसके अलावा कार्यपालन अभियंता श्री श्रीवास ने टीम के साथ ग्राम मदनपुर में डोर-टू-डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान मौके पर ही 6 उपभोक्ताओं का पंजीयन कराया गया। विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें।समाधान योजना 2026 के तहत आयोजित ये शिविर उपभोक्ताओं के लिए राहत देने के साथ-साथ विभाग और जनता के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण भी बन रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

स्कोडा ऑटो इंडिया ने ईज़ी टू लव नईकुशाक के लॉन्च के साथ वैल्यू, परफॉर्मेंस और सेफ्टी कोनए सिरे से परिभाषित किया है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने रिफ्रेश्ड और अपग्रेडेड नई कुशाक की कीमतों औरकस्टमर डिलीवरी शुरू होने की घोषणा कर दी है। इस साल जनवरी में लॉन्चहुई नई कुशाक, वैल्यू, सेफ्टी, ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में सबसे आगेहै और पूरी रेंज में यूरोपियन टेक्नोलॉजी को सबके लिए लाने की ब्रांड कीस्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाती है। सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी जैसे बिल्कुल नयाएट-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, रियर सीट मसाजर, और कईनए फीचर्स के साथ-साथ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ, नई कुशाक 1.0 TSI और नई कुशाक 1.5 TSI दोनों ही स्कोडा ऑटो इंडिया की यूरोपियनइंजीनियरिंग और 5-स्टार सेफ्टी को भारतीय सड़कों पर ज़्यादा आसानी सेचलने वाली बनाने की स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं। नई कुशाक पांच ट्रिम्स मेंउपलब्ध है: क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो, जोमैनुअल और रियल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजनका ऑप्शन देती है। कस्टमर्स के पास आठ रंगों ङ्क कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, लावा ब्लू, और डीप ब्लैक - में से चुनने का ऑप्शन है, जिसमें तीन बिल्कुल नए रंग शामिल हैं: शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे, और चेरीरेड। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा, स्कोडा मेंहमारा मिशन यूरोपियन टेक्नोलॉजी को सबके लिए उपलब्ध कराना और इसेज़्यादा कस्टमर्स के लिए आसान बनाना है। नई कुशाक के साथ, हम सच मेंपूरी रेंज में वैल्यू को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। नई कुशाक सभी वेरिएंट्समें कॉम्पिटिटिव वैल्यू प्राइसिंग, बेहतर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और ऑल-राउंडपरफॉर्मेंस के ज़रिए सबसे आगे है। सेगमेंट में पहली बार दिए गए फीचर्स जैसेआठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, रियर सीट मसाजर, और ज़रूरी फीचर्सका स्टैंडर्डाइजेशन, एंट्री वेरिएंट से ही शानदार वैल्यू।

भारत की जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 25 में कुल लाभ के रूप में 6.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया

मुंबई: भारत का जीवन बीमा क्षेत्र परिवारों की सुरक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नवीनतम आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल लाभ के रूप में 6.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह आंकड़ा उस समर्थन के स्तर का प्रमाण है जो जीवन बीमा उद्योग भारतीय परिवारों को सुरक्षा से लेकर सेवानिवृत्ति और धन सृजन तक जीवन के विभिन्न चरणों में प्रदान करता है।

इंश्योरेंस अवेयरनेस कमिटी (आईएसी-लाइफ) के चेयरपर्सन कमलेश राव ने जीवन बीमाकर्ताओं के व्यावसायिक दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा, भारत की जीवन बीमा कंपनियों का काम करने का तरीका—जैसा कि उनकी निरंतरता, भुगतान और वित्तीय मजबूती के आंकड़ों से पता चलता है—यह साबित करता है कि जीवन बीमा परिवार के लिए एक 'पैसे के गुल्लक' की तरह है। यह ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसा भी देता है और लंबे समय के लिए सुरक्षा भी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल भुगतान का 92 प्रतिशत हिस्सा 'लिविंग बेनिफिट्स' (यानी पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मिलने वाला पैसा) के रूप में दिया गया है। इससे पता चलता है कि यह उद्योग सिर्फ मौत के बाद सुरक्षा देने वाला साधन नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद साथी है जो परिवारों की आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद करता है। हम अपने अभियानों के ज़रिए लोगों को यह बताएंगे कि जीवन बीमा कैसे उनके परिवार की कमाई को सुरक्षित रख सकता है और भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकता है। कुल भुगतान किए गए लाभों में से 2.33 लाख करोड़ रुपये निकासी और सरेंडर के कारण रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.77 प्रतिशत की वृद्धि है। चूंकि निरंतरता अनुपात मजबूत बना हुआ है, इसलिए यह नियोजित जीवनचक्र निकास को दर्शाता है। पॉलिसीधारक अपने परिवारों के जीवन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों की शैक्षणिक पढ़ाई, अपना घर खरीदना, विदेशी छुट्टियों का आनंद लेना आदि। हालांकि, जीवन बीमा को हमेशा इसके वित्तीय सुरक्षा भाग के लिए उच्च सम्मान प्राप्त रहा है, लेकिन अब नीतियों के लाभार्थी अन्य मूल्यवान उद्देश्यों के लिए भी पॉलिसी से प्राप्त राशि का उपयोग कर रहे हैं। जीवन बीमा के उत्पाद पोर्टफोलियो के विकास, जिसमें अब बच्चों की योजनाएं, वार्षिकी नीतियां, बाजार से जुड़े लाभ आदि शामिल हैं, का अर्थ है कि उपभोक्ता अपने जीवन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पॉलिसी से प्राप्त राशि को नई पॉलिसी में फिर से निवेश कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग में 30 लाख रूपए का भत्ता, 200 संशोधन अनुकंपा में फर्जीवाड़ा कर किया घोटाला : अंकित गौरहा

बिलासपुर। सवाल है कि इतनी बड़ी राशि का आहरण, वितरण बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। स्थापना शाखा के जूनियर ऑडिटर के खिलाफ विस्तृत लिखित शिकायत सौंपी है, शिकायत में वित्तीय गबन, अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, युक्तियुक्तकरण में नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर फैसले लेने जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। बिलासपुर जिला शिक्षा विभाग पर गंभीर और बहुस्तरीय भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंकित गौरहा ने प्रदेश के प्रमुख सचिव से मुलाकात कर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे और स्थापना शाखा के जूनियर ऑडिटर सुनील यादव के खिलाफविस्तृत लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में वित्तीय गबन, अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, युक्तियुक्तकरण में नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर फैसले लेने जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं।

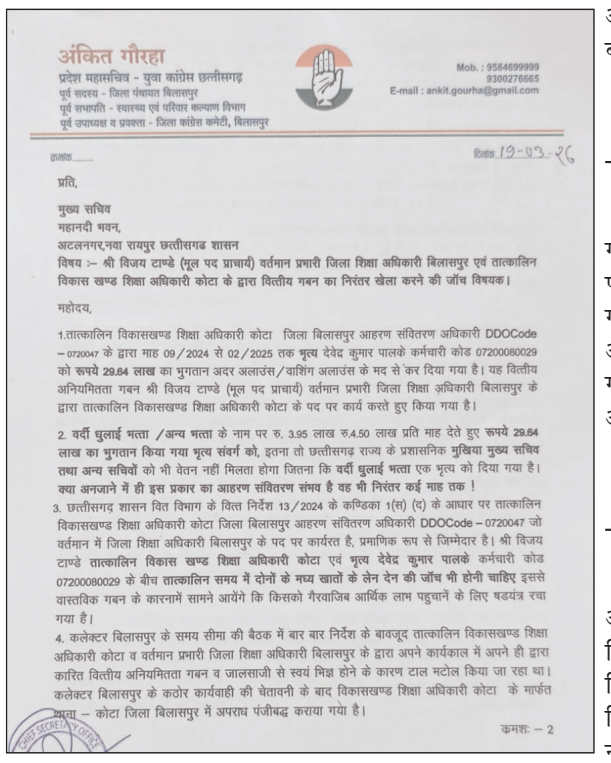

अंकित गौरहा
प्रदेश महासचिव - युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़
पूर्व सदस्य - जिला पंचायत बिलासपुर
पूर्व सभापति - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
पूर्व उपाध्यक्ष व प्रवक्ता - जिला कांग्रेस कमेटी, बिलासपुर

Mob. : 9584699999
9300276665
E-mail : ankit.gourha@gmail.com

क्रमांक......   दिनांक 19-03-26

प्रति,

मुख्य सचिव
महानदी भवन,
अटलनगर,नवा रायपुर छत्तीसगढ शासन

विषय :- श्री विजय टाण्डे (मूल पद प्राचार्य) वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर एवं तात्कालिन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा के द्वारा वित्तीय गबन का निरंतर खेला करने की जॉच विषयक।

महोदय,

1.तात्कालिन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा जिला बिलासपुर आहरण संवितरण अधिकारी DDOCode – 0720047 के द्वारा माह 09/2024 से 02/2025 तक भृत्य देवेद्र कुमार पालके कर्मचारी कोड 07200080029 को रूपये 29.64 लाख का भुगतान अदर अलाउंस/वाशिंग अलाउंस के मद से कर दिया गया है। यह वित्तीय अनियमितता गबन श्री विजय टाण्डे (मूल पद प्राचार्य) वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा तात्कालिन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा के पद पर कार्य करते हुए किया गया है।

2. वर्दी धुलाई भत्ता /अन्य भत्ता के नाम पर रु. 3.95 लाख रु.4.50 लाख प्रति माह देते हुए रूपये 29.64 लाख का भुगतान किया गया भृत्य संवर्ग को, इतना तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवों को भी वेतन नहीं मिलता होगा जितना कि वर्दी धुलाई भत्ता एक भृत्य को दिया गया है। क्या अनजाने में ही इस प्रकार का आहरण संवितरण संभव है वह भी निरंतर कई माह तक !

3. छत्तीसगढ़ शासन वित विभाग के वित्त निर्देश 13/2024 के कण्डिका 1(स) (द) के आधार पर तात्कालिन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा जिला बिलासपुर आहरण संवितरण अधिकारी DDOCode – 0720047 जो वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पद पर कार्यरत है, प्रमाणिक रूप से जिम्मेदार है। श्री विजय टाण्डे तात्कालिन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा एवं भृत्य देवेद्र कुमार पालके कर्मचारी कोड 07200080029 के बीच तात्कालिन समय में दोनों के मध्य खातों के लेन देन की जॉच भी होनी चाहिए इससे वास्तविक गबन के कारनामें सामने आयेंगे कि किसको गैरवाजिब आर्थिक लाभ पहुचानें के लिए षडयंत्र रचा गया है।

4. कलेक्टर बिलासपुर के समय सीमा की बैठक में बार बार निर्देश के बावजूद तात्कालिन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा व वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा अपने कार्यकाल में अपने ही द्वारा कारित वित्तीय अनियमितता गबन व जालसाजी से स्वयं भिज्ञ होने के कारण टाल मटोल किया जा रहा था। कलेक्टर बिलासपुर के कठोर कार्यवाही की चेतावनी के बाद विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोटा के मार्फत थाना – कोटा जिला बिलासपुर में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।

क्रमशः – 2

CHIEF SECRETARY OFFICE

वर्दी धुलाई, भत्तों के नाम पर 30 लाख का भुगतान

अंकित गौराहा के अनुसार, कोटा विकासखंड में पदस्थ रहते हुए विजय टांडे ने सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच विभाग के एक कर्मचारी देवेंद्र कुमार फाल्के को कर्मचारी कोड के माध्यम से सीधे लगभग 30 लाख रुपए का भुगतान किया। यह राशि अन्य भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता के नाम पर दी गई। आरोप है कि हर महीने लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए तक एक ही कर्मचारी को दिए गए, जो सामान्य वेतन ढांचे से कई गुना अधिक है। सवाल उठाया गया है कि इतनी बड़ी राशि का आहरण और वितरण बिना मिलीभगत के संभव नहीं है।

आहरण संवितरण अधिकारी की भूमिका पर सवाल

शिकायत में कहा गया है कि उस समय विजय टांडे ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी भी थे, इसलिए यह पूरा भुगतान उनकी जानकारी और अनुमति से हुआ। अंकित गौरहा ने मांग की है कि संबंधित कर्मचारी और अधिकारी के बीच खातों के लेन-देन की विस्तृत जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक आर्थिक लाभ और षड्यंत्र का खुलासा हो सके।

कलेक्टर के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं

मामले को कलेक्टर बिलासपुर की समय-सीमा बैठकों में उठाया गया और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बाद में थाना कोटा में अपराध दर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद विजय टांडे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में इसे प्रशासनिक उदासीनता बताया गया है।

कारनामे छिपाने के लिए अधीनस्थों को निलंबित

अंकित गौरहा ने आरोप लगाया है कि अपने कार्यकाल की अनियमितताओं को छिपाने के लिए विजय टांडे ने संबंधित क्लर्क और भृत्य को निलंबित कर दिया, जबकि वास्तविक जिम्मेदारी उन्हीं की थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिला शिक्षा कार्यालय के कुछ अन्य कर्मचारी भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं।

मासिक व्यय पत्रक और बजट में हेरफेर

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि जिला शिक्षा कार्यालय में जमा होने वाले मासिक व्यय पत्रक और बजट दस्तावेजों में गड़बड़ी कर गबन की राशि को छुपाया गया। हस्ताक्षरयुक्त हार्ड कॉपी जमा होने के बावजूद वास्तविक वित्तीय स्थिति अलग रखी गई।

पुराने मामलों में भी कार्रवाई नहीं, उल्टा पदोन्नति

अंकित गौरहा ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। पूर्व में सहायक ग्रेड-2 राजेश कुमार प्रताप के मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन उसी प्रकरण में विजय टांडे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, दिवंगत शिक्षक पुष्कर भारद्वाज की पत्नी नीलम भारद्वाज द्वारा रिश्वत मांगने की शपथ-पत्र सहित शिकायत की गई थी, जो जांच में सही पाई गई। संबंधित बाबू को निलंबित किया गया, लेकिन विजय टांडे के खिलाफ जांच की अनुशंसा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में उन्हें प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया।

नियुक्ति में नियमों की धज्जियां,अपात्रों को लाभ

शिकायत में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि पात्र परिजनों की जगह अन्य लोगों को नियुक्ति दी गई। इस प्रक्रिया में नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इसमें सुनील यादव की भूमिका को भी अहम बताया गया है।

200 प्रकरणों में संशोधन समितियों को दरकिनार

युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया में भी भारी अनियमितता का आरोप है। जिला स्तरीय और विकासखंड स्तरीय समितियों के अनुमोदन के बिना ही करीब 200 शिक्षक प्रकरणों में संशोधन किए गए। आदेशों में न तो हस्ताक्षर हैं, न नोटशीट और न ही संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई। कई मामलों में न्यायालय के निर्देश का हवाला दिया गया, जबकि अधिकांश संशोधन गोपनीय तरीके से किए गए और बाद में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया गया।

क्या समितियां सिर्फकागजों में.?

अंकित गौरहा ने सवाल उठाया है कि जब समितियां अस्तित्व में हैं,तो उनके बिना निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं या फिर उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। शिकायत में इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया गया है, जिसमें विजय टांडे और उनके करीबी सुनील यादव की केंद्रीय भूमिका है।

जांच प्रभावित होने की आशंका, निलंबन की मांग

शिकायत में यह भी कहा गया है कि विजय टांडे के खिलाफपहले से कई मामलों की जांच चल रही है, जिन्हें पद पर रहते हुए प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए उन्हें तत्काल निलंबित कर स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। सुनील यादव के खिलाफ भी साक्ष्य सहित शिकायत सौंपी गई है।

विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण का संदेश-रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स ने दिखाई सक्रिय भागीदारी

बिलासपुर। दिनांक 22 मार्च 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ङ्क वीर आज़ाद समूह द्वारा विश्व जल दिवस बड़े उत्साह एवं सभी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला मुख्यालय के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में जल जागरूकता रैली के साथ हुई। इस रैली के दौरान स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा 'जल है तो कल है' और ÒSave Water, Save LifeÓ जैसे नारों एवं स्लोगन के माध्यम से आसपास के निवासियों और राहगीरों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। प्रतिभागियों ने लोगों को दैनिक जीवन में जल के सही उपयोग, अपव्यय रोकने तथा भविष्य के लिए जल बचाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात जल ही जीवन है विषय पर तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता

आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता की विशेषता यह रही कि प्रतिभागियों को क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने की स्वतंत्रता दी गई, जिससे कार्यक्रम और अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बन गया।

इस अवसर पर सम्मानित लीडर्स ने भी जल संरक्षण के विषय में अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। इसके बाद सभी स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स एवं लीडर्स को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का समापन वॉटर कमिटमेंट पोस्टर पर हस्ताक्षर कर सभी प्रतिभागियों द्वारा जल संरक्षण एवं जागरूकता फैलाने के सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। यह कार्यक्रम श्री अनुराग कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जिला आयुक्त (स्काउट) तथा श्रीमती नेहा सिंह, जिला आयुक्त (गाइड) के मार्गदर्शन में, श्री संजय मेश्राम, जिला सचिव एवं श्री दिनेश कुमार यादव, जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) की उपस्थिति में, तथा श्री दिलीप कुमार स्वाईं, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) एवं श्रीमती सुजाता सिंह, जिला संगठन आयुक्त (गाइड) के नेतृत्व में संपन्न हुई।

ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के अंतर्गत पेंड्रा रोड स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली का सफल कमीशनिंग

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया है। यह उपलब्धि ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी। यह कार्य दिनांक 22 मार्च 2026 (रविवार) को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) ब्लॉक के दौरान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उल्लेखनीय है कि सामान्यत: किसी भी इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान रेल परिचालन प्रभावित होता है, किन्तु इस कार्य को बेहतर प्रबंधन एवं प्लानिंग के तहत मात्र लगभग 5:30 घंटे में पूर्ण कर लिया गया, जिससे रेल परिचालन को न्यूनतम प्रभावित करते हुए सुचारु बनाए रखा गया। नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के अंतर्गत 40 प्वाइंट्स एवं 226 रूट्स का प्रावधान किया गया है, जिससे स्टेशन की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सिग्नलिंग व्यवस्था में 22 मुख्य सिग्नल, 17 कॉलिंग-ऑन सिग्नल तथा 75 डमी प्वाइंट्स शामिल किए गए हैं। आधुनिकीकरण के तहत, स्टेशन पर 06 लाइनों में 66 डीसी ट्रैक सर्किट के साथ-साथ कुल 54 एमएसडीएसी (मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर) ट्रैक सेक्शन स्थापित किए गए हैं। यह उन्नत व्यवस्था ट्रेन की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के साथ-साथ सिग्नलिंग प्रणाली में अतिरिक्त विश्वसनीयता एवं बैकअप प्रदान करेगी। इस परियोजना में अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (सिमेन्स), डेटा लॉगर, फायर अलार्म सिस्टम, एमएसडीएसी (मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर), फ्यूज चेंजओवर एवं अलार्म सिस्टम तथा आईपीएस (इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई) जैसी उन्नत प्रणालियाँ शामिल हैं। उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली में आधुनिक रूट सेटिंग सुविधा, बेहतर पॉइंट ऑपरेशन मैकेनिज्म तथा अत्याधुनिक संरक्षा विशेषताएँ शामिल हैं, जो न केवल ट्रेनों के सुगम संचालन को सुनिश्चित करेंगी, बल्कि यातायात वहन क्षमता में भी वृद्धि करेंगी।

देश के औद्योगिक विकास को गति देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियां..............

■ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा माल राजस्व अर्जन एवं नेट टन किलोमीटर में नए कीर्तिमान

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए माल ढुलाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। देश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करते हुए रेलवे ने दिनांक 21 मार्च 2026 को मात्र 355 दिनों में ही अब तक का सर्वाधिक ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू (मूल माल राजस्व) अर्जित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 (365 दिनों) की तुलना में 10 दिन पहले प्राप्त की गई है। दिनांक 22 मार्च 2026 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ?29,493.59 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू अर्जित किया गया है, जो इसकी उत्कृष्ट कार्यक्षमता एवं माल परिवहन में अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल में सर्वाधिक ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू अर्जित करने वाला ज़ोन बनकर उभरा है तथा इस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल के कुल माल राजस्व में इसका 17.13त्न का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही, गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6त्न (?1026 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसी क्रम में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 20 मार्च 2026 को मात्र 354 दिनों में अब तक का सर्वाधिक एनटीकेएम (नेट टन किलोमीटर) अर्जित करते हुए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि भी पिछले वर्ष की तुलना में 11 दिन पहले प्राप्त की गई है। दिनांक 22 मार्च 2026 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 146.75 बिलियन एनटीकेएम (नेट टन किलोमीटर) का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा प्राप्त कर भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस वर्ष 146 बिलियन से अधिक एनटीकेएम (नेट टन किलोमीटर) का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करते हुए

भारतीय रेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही, पिछले वर्ष की तुलना में 5.4 बिलियन नेट टन किलोमीटर (3.8त्न) की वृद्धि दर्ज की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास के कार्य भी तीव्र गति से किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण रेलखंडों में तीसरी एवं चौथी रेल लाइनों की कमीशनिंग की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेनों की गतिशीलता एवं परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे माल यातायात को सुगम बनाने के साथ-साथ समयबद्धता में भी सुधार हुआ है। माल यातायात के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। त्योहारों, छुट्टियों एवं विशेष अवसरों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अधिकाधिक आरक्षित बर्थ एवं सीट उपलब्ध कराने हेतु विशेष ट्रेनों का सफलतापूर्वक परिचालन किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, कुशल संचालन, उन्नत प्रबंधन प्रणाली एवं माल ढुलाई में निरंतर सुधार का परिणाम है। महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के कुशल निर्देशन एवं सतत प्रोत्साहन में यह उपलब्धियाँ और अधिक सुदृढ़ हुई हैं।

विराट ने आईपीएल से पहले आरसीबी को किया सावधान

डिफेंडिंग चैंपियन को सभी टीमें हमें हराना चाहेंगी

आईपीएल में आरसीबी का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि इस बार का सत्र पहले से कठिन होगा। इसलिए टीम के सभी खिलाड़ियों को और अधिक गंभीरत से खेलना होगा। विराट ने कहा कि इस बार सभी टीमें आरसीबी को हराने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी क्योंकि वह मौजूदा चैम्पियन है। ऐसे में सभी टीमें हमारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। इस माह के अंत में शुरु हो रहे आईपीएल में आरसीबी का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आरसीबी के शेयर किए गए एक वीडियो में विराट टीम के खिलाड़ियों से बात करने के दौरान उन्हें उत्साहित करते दिखे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 सत्र में टीम ने काफी मेहनत की है और उसी मेहनत के कारण उन्हें पिछले सत्र में खिताबी जीत मिली थी।

विराट ने खिलाड़ियों से कहा कि इस बार चुनौती और बड़ी होगी, इसलिए शुरुआत से ही पूरी ताकत से खेलना होगा। कोहली ने कहा, हमने पिछले 2-3 साल में जो हासिल किया, उसके लिए बहुत मेहनत की पर अब चुनौती और कठिन होने वाली है क्योंकि बाकी टीमें हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। हमें अभी से स्विच ऑन होना होगा और हर सेशन में आना सौ फीसदी से अधिक देना होगा।

आरसीबी ने साल 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। तब उसने फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था। अब टीम आईपीएल 2026 में अपने खिताब का बचाव करने का पूरा प्रयास करेगी और लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी। टीम के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने कहा कि इस बार नीलामी में टीम ने काफी अच्छे खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिससे टीम पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ियों को टीम के माहौल में ढालना और सीनियर खिलाड़ियों के साथ सही तालमेल बनाना इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। गौरतलब है कि विराट आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने आईपीएल में 267 मैचों में 8661 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल में अब विराट कोहली इस सत्र मे भी अधिक से अधिक रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने के साथ ही नये रिकार्ड अपने नाम करना चाहेंगे।

अंतिम बार लीग से खेलते दिखेंगे

धोनी के इस बार आईपीएल से संन्यास लेने की अटकलें तेज

चेन्नई। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी 44 साल के हो गये हैं। ऐसे में उनके संन्यास की अटकलें जोर पकड़ती जा रही हैं। इस बार माना जा रहा है कि वह अंतिम बार लीग से खेलते दिखेंगे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वह स्टेडियम में पहुंचे तो हर तरफ से 'थाला थाला' सुनाई देना लगा। उनकी आवाज सुनकर प्रशंसक भी भावुक दिखे। वहीं धोनी पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और डीजे ब्रावो के साथ नजर आये। इससे भी प्रशंसकों को लगा रहा है कि ये धोनी का अंतिम आईपीएल रहेगा।

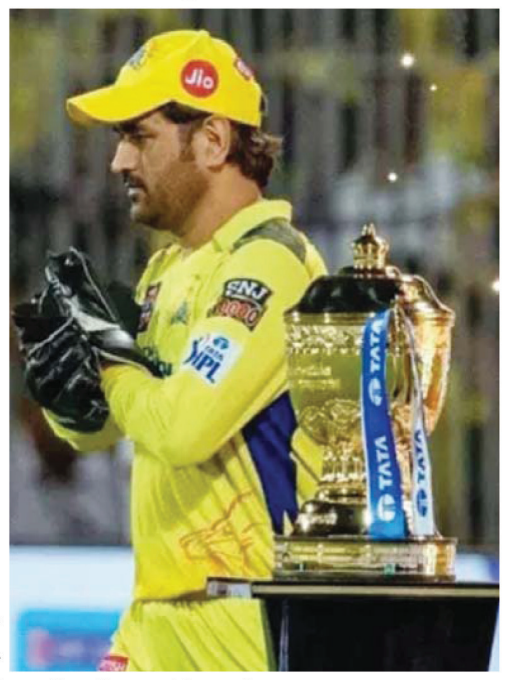

प्रशंसक सीएसके के 'रोर 26' इवेंट के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे। कुछ सीएसके खिलाड़ियों ने मैदान पर अभ्यास किया, वहीं कुछ बातें करते दिखे। वहीं पहली बार टीम में शामिल जब नए खिलाड़ी संजू सैमसन जब मैदान में आए, तब भी जोरदार तालियां बज उठीं।

धोनी आईपीएल में अपना 19वां सत्र खेलने जा रहे हैं। उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही पर सीएसके के लिए वह आज भी सबसे कीमती खिलाड़ी हैं हालांकि अब वह निचले स्तर पर ही बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। वहीं चेन्नई के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का मानना है कि धोनी का ये अंतिम आईपीएल रहेगा।

उथप्पा ने कहा, 'आईपीएल 2026 शायद उनका आखिरी साल होगा। मुझे लगता है कि इस साल वह मेंटर-कम-खिलाड़ी की भूमिका में रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वह इस बार नंबर सात पर बल्लेबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि वह नंबर आठ पर बल्लेबाजी करेंगे। वह जानते हैं कि वह धीरे-धीरे बाहर हो रहे हैं, इसलिए अपनी को टीम से अलग कर रहे हैं ताकि उनके बिना भी टीम जीत सके। वह जानते हैं कि तभी कप्तान के तौर पर रुतुराज गायकवाड़ की क्षमता का पता चल सकेगा।, '

आरसीबी को शुरुआती मैचों में हेजलवुड की कमी खलेगी : श्रीकांत

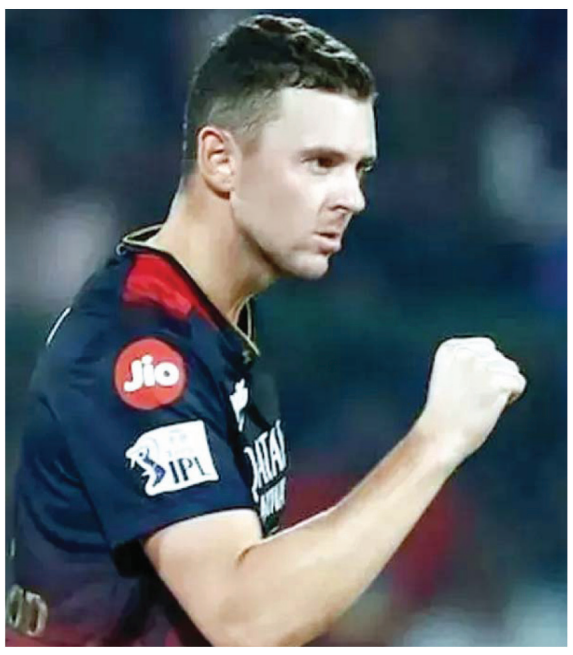

मुम्बई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आईपीएल 2026 में शुरुआती मैच में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की कमी खेलेगी। इसका कारण है कि पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण हेजलवुड शुरु के मैचों में नहीं खेल पायेंगे। ऐसे में रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी के लिए हेजलवुड की कमी पूरी करना आसान नहीं रहेगा। श्रीकांत ने कहा है कि इस तेज गेंदबाज का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेजलवुड ने पिछले सत्र में 12 मैचों में 22 विकेट लिए थे। तब उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन देकर 4 विकेट था। यही वजह है कि श्रीकांत ने हेजलवुड के नहीं होने को आरसीबी के लिए करारा झटका माना है। हेजलवुड चोटिल होने के कारण पिछले साल नवंबर के बाद से ही पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं। वह एशेज सीरीज और टी20 विश्वकप भी नहीं खेल पाये। हैमस्ट्रिंग के बाद उनको एंकल इंजरी का सामना करना पड़ा। श्रीकांत ने एक वीडियो में कहा, हेजलवुड का न होना एक बड़ा झटका है। अगर वह दो सप्ताह भी फिट नहीं होते, तो भी वे वहां तीन से चार मैच खेल लेते। उनके बिना, टीम की गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी। उनका कोई भी विकल्प नहीं है। जैकब डफी भी खराब गेंदबाज नहीं है पर विश्व कप में वह विफल रहे थे। यह देखना होगा कि वह आईपीएल में चल पाते है या नहीं।उन्होंने साथ ही कहा, हेजलवुड के बिना आरसीबी की 25 फीसदी उम्मीद कम हो वह न सिर्फ गेम-चेंजर हैं, बल्कि मैच-विजेता भी हैं। वह जो डर पैदा करता हैं, वह बुमराह जैसा ही है। हेजलवुड उस शानदार टेस्ट मैच लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जहां बल्लेबाज आगे या पीछे नहीं जा सकता।

सीएसके ने रैना और हेडन को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया

रैना, सीएसके में 'चिन्ना थाला' के नाम से भी लोकप्रिय रहे हैं

चेन्नई। पांच बार कि आईपीएल खिताब विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) ने आईपीएल के 19 वें सत्र की शुरुआत से पहले प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिये। चेपॉक स्टेडियम में आयोजित 'रोर 26' नाम के एक कार्यक्रम में ये पुरस्कार टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना और मैथ्यू हेडन दो दिया गया। रैना, सीएसके में 'चिन्ना थाला' के नाम से भी लोकप्रिय रहे हैं। वह सीएसके की ओर से सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते हैं। उन्होंने साल 2008 से 2021 तक टीम की ओर से 2010, 2011, 2018 और 2021 में जीत हासिल की है। रैना अभी भी सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 5,529 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 चैंपियंस लीग टी20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता था।

वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबा हेडन ने साल 2008 से 2010 तक सीएसके की ओर से खेलते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हेडन साल 2009 में सीएसक की ओर से औरेंज कैप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तब उन्होंने 572 रन बनाए थे। उन्होंने सीएसके की ओर से कुल 1,117 रन बनाए और 8 अर्धशतक लगाए। वह 2010 में आईपीएल जीतने वाली टीम में भी शामिल थे। 'रोर 26' इवेंट इस समारोह में मुथैया मुरलीधरन , अंबाति रायडू सहित पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए।

लिविंगस्टोन को ज्यादा मोटी रकम देकर गलती की : आकाश

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी को मोटी रकम देकर अपने साथ जोड़कर गलती की है। आकाश ने कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो लीग में असफल रहा है उसपर 13 करोड़ की रकम लगाना समझ में नहीं आता। इससे कम राशि में तो कोई अच्छा खिलाड़ी मिल जाता। चोपड़ा के अनुसार पिछले तीन साल में उन्होंने इस खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा है। इस दौरान जिस भी लीग में वह रहा उसे पैसे की कीमत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जिस खिलाड़ी को खराब प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड की टीम ने बाहर कर दिया उसके लिए आईपीएल में अपने को साबित करना कठिन रहेगा। उससे अपने प्रदर्शन से दिखाना होगा कि वह दी जा रही रकम का अधिकारी है। एक वीडियो में आकाश ने कहा, मैं लियाम लिविंगस्टोन के बारे में सोच रहा हूं। वह इंग्लैंड टीम में संवाद की कमी के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें सही संदेश नहीं मिले थे उन्हें अब सनराइजर्स ने बहुत सारे पैसे में खरीद लिया है पर उनके आंकड़े इस लायक नहीं थे। उन्होंने पिछले दो या तीन सालों में ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्हें इतने पैसे मिलें।उन्होंने कहा, अब जब वह वहां आ गये है, तो उसे खेलने और कुछ अलग करने का अवसर मिलेगा। साथ ही कहा कि उसे इस मौके को भुनाना होगा। लिविंगस्टोन ने साल टी20 विश्व कप 2026 के बाद इंग्लैंड मैनेजमेंट पर सवाल भी उठाए थे। आकाश ने यह भी कहा है कि युवा अभिषेक शर्मा के पास इस सत्र में अधिक से अधिक रन बनाकर लय हासिल करने और ईशान किशन के पास अपनी कप्तानी साबित करने का अवसर है। ईशान को नियमित कप्तान पैट कमिंस के फिट नहीं होने के कारण शुरुआती मैचों के लिए कप्तानी दी गयी है।

पीटरसन की पसंदीदा आईपीएल टीम में रोहित को नहीं मिली जगह

मुम्बई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने आईपीएल की अपनी पसंदीदा टीम बनायी है। हैरानी की बात ये है कि पीटरसन की इस टीम में आक्रामक बल्लेबाज रोहित शर्मा को जगह नहीं मिली है जबकि रोहित आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस ने पांच बार खिताब जीता है। वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। पीटरसन ने अपनी इस टीम में पारी की शुरुआत के लिए क्रिस गेल और विराट कोहली को चुना। इसके बाद, उन्हें एबी डी विलियर्स, सुरेश रैना, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, ऋषभ पंत, युवराज सिंह और कीरोन पोलार्ड में से तीन मध्य क्रम के खिलाड़ी चाहिये थे। इस पर पीटरसन ने रैना और डी विलियर्स को शामिल किया पर तीसरे खिलाड़ी का नाम नहीं बताया। वहीं कप्तान और विकेटकीपर के लिए उन्होंने महेन्द्र सिंह धोनी को शामिल किया। बल्लेबाजी क्रम में उन्होंने धोनी को पांचवें 5वें नंबर पर रखा है। ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें हार्दिक पांड्या, सुनील नरेन, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्राव और आंद्रे रसेल में से दो खिलाड़ियों को चुनने का मौका था तो उन्होंने रसेल को शामिल किया। साथ ही नरेन और जडेजा को भी शामिल किया। वहीं एक स्पिनर के लिए राशिद खान, हरभजन सिंह और युजी चहल में से पीटरसन ने चहल को शामिल करते हुंए कहा कि कि वह मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। इसके बाद दो तेज गेंदबाजों के लिए जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा के नाम रखे गये और पीटरसन ने दोनो को ही शामिल कर लिया। इसके बाद जो टीम बनी वह इस प्रकार है : क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सुरेश रैना, एमएस धोनी, सुनील नरेन, रवींद्र जड़ेजा, आंद्रे रसेल, युजी चहल, जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा।

आईपीएल से युवाओं को मिली पहचान पर अनुभवी खिलाड़ियों का जलवा बरकरार

मुम्बई। इस माह के अंत में शुरु हो रहे आईपीएल से एक बार फिर उभरते हुए खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिलेगा। आईपीएल से कई युवा खिलाड़ियों को पहचान मिली है और कई खिलाड़ी भारतीय टीम में भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। इनमें रिंकू सिंह से लेकर अभिषेक शर्मा सहित कई अन्य खिलाड़ी भी है। आईपीएल से पहचान और नये अवसरों के साथ ही युवाओं को मोटी रकम भी मिलती है। भारतीय टीम में चयन न होने वाले खिलाड़ी भी इस लीग से इतना कमा लेते हैं कि अच्छे से अपनी जिंदगी चला सकते हैं।

आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले जहां युवा खिलाड़ी अपनी फिटनेस और आक्रामक खेल से छाये हुए रहे हैं तो दूसरी ओर अनुभवी खिलाड़ी भी इस लीग में अपने प्रदर्शन से दिखाते रहे हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं। इसमें कई अनुभवी खिलाड़ियों ने मैच विजेता पारियां खेलकर मैच का रुख बदला है। इनमें आरसीबी के विराट कोहली से लेकर मुम्बई इंडियंस के रोहित शर्मा और सीएसके के महेन्द्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी हैं, जो आज भी अकेले मैच का रुख पलट सकते हैं.

रोहित शर्मा (38 साल) : रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड पांच बार ट्रॉफी जीती है। वह मुंबई इंडियंस के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं। अब भले ही कप्तानी युवा हार्दिक पंड्या संभाल रहे हों पर रनों की जिम्मेदारी रोहित पर ही है।

विराट कोहली (37) : विराट कोहली आईपीएल की शुरुआत से आरसीब का हिस्सा हैं।विराट कोहली का खिताब का सपना आईपीएल 2026 में आरसीबी के चैंपियन बनने के साथ पूरा हुआ। फिटनेस और फॉर्म में वह किसी भी युवा खिलाड़ी पर भारी ही पड़ते नजर आएंगे।

महेन्द्र सिंह धोनी (44 साल): महेंद्र सिंह की कप्तानी में टीम ने पांच बार खिताब जीता है। अब भले ही कप्तानी रितुराज गायकवाड़ संभाल रहे हैं पर धोनी का मार्गदर्शन उसमें अहम रहता है। धोनी सीएसके के आधार स्तंभ हैं।

भुवनेश्वर कुमार (36 साल): स्विंग के महारथी भुवनेश्वर कुमार 36 साल की उम्र में भी जबरदस्त लाइन-लैंथ से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना हो या डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालना, भुवी उसमें युवा गेंदबाजों से अधिक तेज हैं।

रवींद्र जडेजा (37 साल : जडेजा अगर भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास के सबसे फिट खिलाड़ी हैं। जड्डू को देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह 37 साल के हो चुके हैं। किफायती गेंदबाजी, उपयोगी बल्लेबाजी के साथ-साथ हैरतंगेज फील्डिंग करने वाले रवींद्र एक टीम के लिए पूरा पैकेज हैं। जडेजा की घर वापसी हुई है, वह अपनी सबसे पहली टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने के लिए तैयार हैं।

सुनील नरेन- सुनील नरेन (37 साल) : सुनील नरेन का नाम आते ही बल्लेबाजों के मन में डर बैठ जाता है। 37 की उम्र में भी उनकी मिस्ट्री स्पिन का जादू बरकरार है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह तेजतर्रार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है।

विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश सड़क, बिजली, पानी से लेकर स्वास्थ्य-शिक्षा तक योजनाओं की गहन समीक्षा

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए कलेक्टर संबित मिश्रा ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।कलेक्टर ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नक्सल पीड़ित परिवारों पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने हेतु आवश्यक दस्तावेज सरलता से उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही नियद नेल्लानार क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।बैठक में आश्रम छात्रावास एवं आवासीय शैक्षणिक संस्थानों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य जांच की सतत रिपोर्टिंग करने को कहा गया। वहीं बालिका आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीसीटीवी कैमरे और बाउंड्री वॉल अनिवार्य करने तथा जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले के सभी विकासखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निर्धारित तिथियों में जांच एवं उपचार किया जा रहा है। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. बी.आर. पुजारी को निर्देशित किया कि विशेषज्ञों की उपस्थिति की जानकारी समयपूर्व संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ ले सकें। बैठक में डीएफओ रमेश कुमार जांगड़े, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कोरबा में कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

कोरबा /मूक पत्रिका

जिले में युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल आधारित उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से 18 दिवसीय कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वेल्डिंग कौशल पर आधारित है, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों को तकनीकी दक्षता के साथ-साथ उद्यम स्थापना एवं संचालन से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद की संयुक्त पहल है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता की भावना को विकसित करना तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है।

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी कौशल और उद्यमिता का समन्वय ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकता है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, नियमितता और नवाचार की भावना को अपनाने पर विशेष जोर दिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं एवं महिलाओं में उद्यमिता की भावनाओं को जागृत करना है, ताकि वे रोजगार की तलाश करने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बन सकें। साथ ही यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को वेल्डिंग तकनीक, मशीन संचालन, सुरक्षा उपाय, उत्पाद गुणवत्ता, लागत प्रबंधन, विपणन रणनीति तथा सूक्ष्म उद्यम स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को आत्मविश्वास प्राप्त होगा और वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे।

राशन कार्ड में एंट्री लेकिन अनाज गायब

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। रायगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भातपुर के आश्रित ग्राम दुलोपुर के ग्रामीणों ने उन्हें विगत तीन माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से करते हुए जल्द से जल्द राशन दिलवाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन नहीं मिलने से उन्हें 22 से 25 रूपए किलो की दर से चावल खरीदना पड़ रहा है। तीन माह से राशन नहीं मिलने पर परेशान ग्राम पंचायत भातपुर के आश्रित गांव दुलोपुर के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंच कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उन्हे अपनी व्यथा सुनाई। ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी लोग गरीब परिवार से हैं और रोजी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। पिछले तीन महीने से जनवरी, फरवरी और मार्च का राशन उन्हें अब तक नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें मजबूरी में बाजार से 22 से 25 रुपये प्रति किलो की दर से चावल खरीदना पड़ रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा मामले की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव को भी कई बार दी गई, लेकिन सचिव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और समस्या लगातार बनी रही। वहीं राशन कार्ड में फरवरी माह का राशन दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तविक हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने राशन वितरण में भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई है जिसकी जांच करने व लंबित तीन महीनों का राशन तत्काल उपलब्ध कराने की उन्होने मांग की है ताकि जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके।

कौन किसान,किसका जमीन,उपार्जन केंद्र में बड़ा खेल, दूसरों की जमीन पर धान बेचने का खुलासा, तंत्र पर उठे गंभीर सवाल !

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

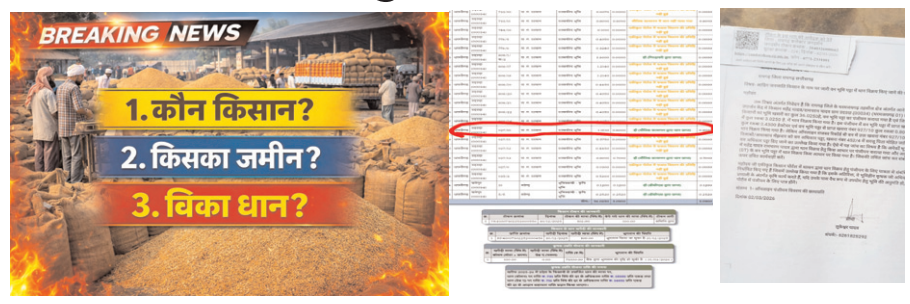

एक ओर किसान अपना धान नहीं बिकने की पीड़ा लेकर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी तंत्र की जमीनी हकीकत पूरी व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने सक्ती जिला प्रशासन और सहकारी समिति को स्पष्ट निर्देश देते हुए किसान का शेष 84 क्विंटल धान 30 दिनों के भीतर खरीदने का आदेश दिया है। न्यायालय की सख्त टिप्पणी रही कि नियमों की आड़ में किसी भी किसान का नुकसान स्वीकार्य नहीं होगा।लेकिन वहीं रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील अंतर्गत दुर्गापुर उपार्जन केंद्र से धान खरीदी व्यवस्था में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे तंत्र की कार्यशैली को कटघरे में ला खड़ा किया है। बता दें, दस्तावेज सत्यापन मामले के अनुसार, ग्राम उदउदा के किसान महेंद्र यादव/रामचरण यादव (00034) (धरमजयगढ़ 01) के नाम पर एकीकृत किसान पोर्टल में कुल 36.0250 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन दर्ज किया गया है। जबकि वास्तविक धान सत्यापन मात्र 3.0250 हेक्टेयर में ही किया गया। यह अंतर अपने आप में संदेह को जन्म देता है और पूरे प्रकरण को संदिग्ध बना देता है। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पंजीयन में शामिल कुछ खसरा नंबर ऐसे हैं, जो दस्तावेज अनुसार वन अधिकार पट्टा के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हैं। खसरा नंबर 452/4 (0.4300 हेक्टेयर) ड्ढ राजू पिता मोहित (मझवार) के नाम दर्ज और खसरा नंबर 927/10 (0.8000 हेक्टेयर) ड्ढ तिलासो/अमरसाय मझवार के नाम दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद, इन जमीनों पर भी महेंद्र यादव/रामचरण यादव के नाम से धान विक्रय किया गया। वहीं दूसरी तरफसवाल यह उठता है कि आखिर किस आधार पर दूसरे भू-स्वामियों की जमीन को अपने नाम पर दर्शाकर पंजीयन कराया गया? और यह मामला केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि एक सुनियोजित गड़बड़ी की ओर इशारा करता है, जिसमें संभवतः जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरे सिस्टम को ही दरकिनार कर दिया गया।

बहरहाल नियमों की बात करें तो एकीकृत किसान पोर्टल में स्पष्ट प्रावधान है कि केवल वही किसान पंजीयन के पात्र हैं, जिनके पास वैध भूमि स्वामित्व या उपयोग की अनुमति हो। अधिया या रेगहा प्रणाली के अंतर्गत खेती करने वालों को भी तभी पात्रता मिलती है, जब उनके पास भूमि उपयोग की वैध अनुमति हो। ऐसे में वन अधिकार पट्टा की भूमि, जो अनुसूचित जनजाति (स्ञ्) के नाम पर सुरक्षित है, उसमें इस तरह का धान विक्रय सीधे-सीधे नियमों की अनदेखी को दर्शाता है। यह पूरा मामला अब जांच की मांग कर रहा है। सवाल सिर्फ एक किसान के पंजीयन का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है, जिसने बिना सत्यापन के इस तरह की गड़बड़ी को होने दिया। लेकिन क्या प्रशासन इस पूरे खेल की तह तक जाएगा?क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?वहीं मामले को लेकर उच्च जिला अधिकारी कलेक्टर को शिकायत की गई है, और संबंधित प्रशासन का कहना है कि उचित जांच कार्रवाई जारी है। फिलहाल, क्षेत्र में इस खुलासे के बाद उन किसानों में आक्रोश का माहौल है,जो अपनी धान नहीं बेच पाए और वहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, और निष्पक्ष जांच कार्रवाई पर निगाहें टिकी हुई है।

सक्ती जिले में मादक पदार्थों की अवैध खेती पर कड़ी नजर, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

सक्ती/मूक पत्रिका

जिले में मादक पदार्थों की अवैध खेती पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए इस पर निरंतर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में संभावित अफीम सहित अन्य अवैध फसलों की पहचान एवं रोकथाम के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी, सचिव और कोटवार की संयुक्त टीम तथा शहरी क्षेत्रों में पटवारी एवं नगरीय निकायों के अमले को मिलकर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर राजस्व, पुलिस और वन विभाग को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कृषि, उद्यानिकी एवं रेशम विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निगरानी में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करने, संदिग्ध फसलों की पहचान करने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रशासन ने अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने ली स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक

आधार आधारित उपस्थिति, एएनसी पंजीयन और संस्थागत प्रसव पर कलेक्टर का सख्त फोकस

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने बीते मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला स्वास्थ्य समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। यह बैठक पहले जारी निर्देशों की प्रगति की समीक्षा तथा जमीनी स्तर पर कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया गया।

आधार आधारित उपस्थिति और 100त्न एएनसी पंजीयन पर विशेष जोर-बैठक में कलेक्टर ने आधार आधारित उपस्थिति, गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन, समय पर जांच और संस्थागत प्रसव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्भवती महिलाओं का प्रारंभिक पंजीयन समय पर होना चाहिए और उनकी सभी निर्धारित जांच पूरी कराई जाए। साथ ही हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी विभाग को समन्वित कार्य के निर्देश-कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों की जानकारी का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। साथ ही सुपोषण अभियान, पोषण पुनर्वास, टीकाकरण सत्रों की नियमितता और संयुक्त फील्ड विजिट को भी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एनसीडी और एचआईवी जांच की भी समीक्षा-बैठक में मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, टीकाकरण, एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज), एचआईवी जांच सहित अन्य प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए और हर विकासखंड स्तर पर सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, पर्याप्त भंडारण और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी-कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या लक्ष्य पूर्ति में शिथिलता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) को निर्देशित किया कि वे विकासखंडवार प्रगति की नियमित समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग बढ़ाएं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर-बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण पुनर्वास, सुपोषण अभियान, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग, टीकाकरण और आंगनबाड़ी-स्वास्थ्य अमले के संयुक्त कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का बेहतर समन्वय ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर, सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी जिला नोडल अधिकारी, सभी बीएमओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जिले को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।

मुख्य अतिथि आशाराम नेताम की उपस्थिति में 04 नए वाटर टैंकरों का लोकार्पण

कांकेर : बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट से

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर / :-गर्मी की दस्तक के साथ ही कांकेर शहर में गहराते जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में नगर पालिका परिषद द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है। स्थानीय घड़ी चौक स्थित फायर स्टेशन परिसर में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में, मुख्य अतिथि आशाराम नेताम की गरिमामयी उपस्थिति में शहरवासियों के लिए 04 नए पानी के टैंकरों का लोकार्पण कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित किया गया। इन टैंकरों को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, डी.एम.एफ (ष्ठरूस्न) मद से 14 लाख की लागत से हुई खरीदी इन 04 पानी टैंकरों की खरीदी डी.एम.एफ मद के अंतर्गत की गई है, जिसकी कुल स्वीकृत लागत राशि ?14.00 लाख है। यह पहल बढ़ती गर्मी के दौरान शहर के उन वार्डों और क्षेत्रों में, जहाँ पाइपलाइन की सुविधा सीमित है या जहाँ पानी का दबाव कम रहता है, सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक ने की। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि आशाराम नेताम के साथ-साथ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा , भाजपा जिला अध्यक्ष महेश जैन , पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समस्त वार्ड पार्षदगण एवं नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ÷हमारा उद्देश्य स्पष्ट है - हर घर तक पानी, हर व्यक्ति तक सुविधा।

जनता की सेवा ही हमारा मुख्य धर्म है और शहर का चहुंमुखी विकास ही हमारा अंतिम लक्ष्य है।÷ यह कदम शहर के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।